

[2023] 10 एससीआर 1221:2023 आई. एन. एस. सी 625

क.

पाश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड v.

रमन आई. एस. पी. ए. टी. प्राइवेट लिमिटेड और ओ. आर. एस. (2019 की सिविल अपील संख्या 7976)

17 जुलाई, 2023

[एस. रवींद्र भाट और दीपांकर दत्ता, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016।238, 53 - एस का प्रबलित प्रभाव।238 - परिसंपत्तियों का वितरण यू/एस।53 - केंद्र या राज्य सरकार की तुलना में सुरक्षित लेनदारों को देय देय राशि:आई. बी. सी. दो विशिष्ट प्रावधानों के बावजूद बिजली अधिनियम, 2003 के प्रावधानों को ओवरराइड करता है जो गैर-अबाधित खंडों (ss.173 और 174) के साथ खुलते हैं-आई. बी. सी. के प्रावधान सुरक्षित लेनदारों को देय बकाया को केंद्र या राज्य सरकार-बिजली अधिनियम, 2003 को देय बकाया से अधिक मानते हैं।173,174.

ग

डी.

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 -एस. 53 (1) (ए)-(एफ)-वाटरफॉल मैकेनिज्म-दावों की प्राथमिकता-परिसंपत्तियों के वितरण का आदेश-"सरकारी बकाया"-कॉर्पोरेट देनदार ने बिजली की आपूर्ति के लिए अपीलकर्ता-पी. वी. वी. एन. एल. के साथ एक समझौता किया-पी. वी. वी. एन. एल. ने कॉर्पोरेट देनदार को बिजली की आपूर्ति के लिए बिल उठाए लेकिन बकाया बकाया रहा-पी. वी. वी. एन. एल. ने कॉर्पोरेट देनदार की संपत्तियों को कुर्क कर दिया-तहसीलदार, बिक्री, दान या किसी अन्य तरीके से संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक लगा दी, और संपत्तियों पर शुल्क भी लगाया-कॉर्पोरेट देनदार ने समाधान प्रक्रिया पूरी की जो सफल नहीं रही और परिसमापन के अधीन हो गई-जिला कलेक्टर ने बकाया राशि की वसूली के लिए नोटिस जारी किया-एन. सी. एल. टी. ने तहसीलदार को निर्देश दिया कि वह बकाया राशि के पक्ष में संपत्ति को तुरंत जारी करे।"सरकारी बकाया "आई. बी. सी. में परिभाषित नहीं है-यह केवल प्रस्तावना में जगह पाता है-हालाँकि, क्या

ई.

च

जी.

एच.

1221 ए.

1222 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

इस तरह के बकाया को 'झरना तंत्र' में लिखा गया है।धारा 53 (1) (ई), जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि "भारत की संचित निधि और राज्य की संचित निधि के कारण प्राप्त होने वाली राशि सहित केंद्र सरकार और राज्य सरकार को देय कोई भी राशि" खंड (ए) से (डी) में वर्णित लेनदारों के वर्ग की प्राथमिकता में कम है।53(1) - केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बकाया की एक अलग गणना या विनिर्देशन मौजूद है, अन्य लेनदारों के अलावा एक वर्ग के रूप में, जिसमें लेनदार भी शामिल हैं, जिनके पास सुरक्षित ब्याज हो सकता है (जिसके संबंध में राशि का भुगतान किया जा सकता है)-ये बकाया अलग हैं और इन्हें सुरक्षित लेनदारों के बकाया से अलग माना जाना चाहिए-इसके अलावा, पी. वी. वी. एन. एल. की निस्संदेह सरकारी भागीदारी है, जो इसे सरकार या 'राज्य सरकार' का हिस्सा नहीं बनाती है-इसके कार्यों को अन्य संस्थाओं, निजी और

सार्वजनिक दोनों द्वारा दोहराया जा सकता है-इसलिए, पी. वी. वी. एन. एल. को देय बकाया या राशि एस. के विवरण में नहीं आती है।53(1)(च)-उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005-सामान्य खंड अधिनियम, 1897-एस. एस.3(8), 3(60).

ग

डी.

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-योजना पर चर्चा की गई।

विद्युत अधिनियम, 2003-उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005-बकाया बिजली, यदि निगमित देनदार की परिसंपत्तियों पर 'शुल्क' है-ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें ऐसा 'शुल्क' लगाया जा सकता है।

ई.

कानून में गठित किया जाए-आयोजित:के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत

बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी परिस्थितियों की जांच की और कहा कि शुल्क का निर्माण आवश्यक रूप से 2003 के अधिनियम या पूर्ण कानून के एक स्पष्ट प्रावधान पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि मूल कानून के तहत अधिकृत उचित रूप से बनाए गए विनियमों द्वारा बनाया जा सकता है-इस प्रकार, वर्तमान मामले में, पी. वी. वी. एन. एल. ने सही तर्क दिया कि आपूर्ति संहिता के खंड 4.3 (एफ) (iv) के आधार पर, पक्षों के बीच समझौते में शर्तों के साथ पढ़ा गया, कॉर्पोरेट देनदार की संपत्तियों पर शुल्क लगाया गया था-एन. सी. एल. टी. के आदेश से यह भी पता चलता है कि यह स्थिति स्वीकार की गई थी-यह एन. सी. एल. ए. टी. के आदेश से स्पष्ट होता है जो स्पष्ट करता है कि पी. वी. वी. एन. एल. भी कानून के अनुसार 'सुरक्षित परिचालन लेनदार' की परिभाषा के तहत आया था-इस निष्कर्ष की पुष्टि अभियुक्त द्वारा की गई थी। दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016।52, 53(1)(ई), (एफ)-सरकारी ऋण, परिचालन ऋण बनाम ए का बकाया

च

जी.

एच.

1223

पास्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड v. रमन आई. एस. पी. ए. टी. प्राइवेट लिमिटेड और ओ. आर. एस.

असुरक्षित वित्तीय लेनदार-अपनी प्रतिभूति छोड़ने वाले सुरक्षित लेनदारों को रखने के लिए तर्क, प्राथमिकता में अधिक-आयोजित:वरीयताओं के पदानुक्रम में इंगित दावों की प्राथमिकता, जलप्रपात तंत्र के तहत सरकारी ऋणों [खंड (ई)] और परिचालन ऋणों [खंड (एफ)] को असुरक्षित वित्तीय लेनदारों के बकाया की तुलना में कम प्राथमिकता देती है-इसके अलावा, एक सुरक्षित लेनदार को देय ऋण, जब भी ऐसे सुरक्षित लेनदार ने "एस में निर्धारित तरीके से प्रतिभूति छोड़ दी है।52" काफी उच्च प्राथमिकता प्राप्त करना (दिवाला समाधान प्रक्रिया लागतों के तुरंत बाद)-जब सुरक्षित लेनदार प्रतिभूति नहीं छोड़ता है, तो दावे की प्राथमिकता कम होती है।53(1)(ई) (ii) "प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन के बाद किसी भी अवैतनिक राशि" के संबंध में-सरकार को देय राशियों (यानी, भारत की संचित निधि या किसी राज्य की संचित निधि में देय) को उसी तरह से क्रमबद्ध किया जाता है जैसे कि सुरक्षित लेनदारों के जो अपने प्रतिभूति ब्याज को नहीं छोड़ते हैं।53(1)(ई) (ii)]-ऊपर बताए गए तर्क पर चर्चा की गई।

ग

विद्युत अधिनियम, 2003-एस.50, 56, 181(2)(x)-उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005-खंड 4.3 (च) (iv), खंड 6.15-उत्तर प्रदेश सरकारी विद्युत उपक्रम (देय वसूली) अधिनियम, 1958 के तहत वसूली तंत्र।

डी.

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 -धारा 53 (1) (च)-भारत का संविधान-अनुच्छेद 265-"सरकारी बकाया"- आयोजित:कोषागार में देय या जमा किए जाने की आवश्यकता, जैसे कर, शुल्क, आदि जो मोटे तौर पर अनुच्छेद 265 के दायरे में आते हैं, 'सरकारी बकाया' हैं और इसलिए एस द्वारा कवर किए जाते हैं।53(1)(च)-जबकि, सांविधिक निगमों को देय देय राशि जो "केंद्र या राज्य सरकार को देय राशि" के विवरण के भीतर नहीं आती है, उदाहरण के लिए कानूनों द्वारा बनाए गए निगमों को देय राशि जिनके पास अलग-अलग न्यायिक इकाई है, लेकिन जिनके बकाया देय सरकारी बकाया नहीं हैं या जो संबंधित समेकित निधियों में देय हैं, वे एक अलग आधार पर हैं।

ई.

च

कम्पनी अधिनियम, 2013-ss.77, 78, 3(31) - परिसमापक की याचिका कि शुल्क के पंजीकरण के बिना यू/एस।77, परिसमापन कार्यवाही के तहत वही अप्रवर्तनीय था-आयोजित:धारा. 78 यह अधिनियमित करती है कि जब कोई कंपनी जिसकी संपत्ति प्रभार के अधीन है, उसे पंजीकृत करने में विफल रहती है, तो प्रभार धारक (या कंपनी की संपत्तियों पर शुल्क का हकदार व्यक्ति) इसका पंजीकरण कर सकता है -धारा 3 (31) "सुरक्षा हित" को व्यापक शब्दों में परिभाषित करता है- परिसमापक इसका आग्रह नहीं कर सकता है।

जी.

एच.

1224 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

क.

इस स्तर पर, एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के समवर्ती निष्कर्षों के कारण कि पी. वी. वी. एन. एल. एक सुरक्षित लेनदार है-इसके अलावा, तथ्यों पर, परिसमापक की प्रस्तुतियों और शुल्कों के गैर-पंजीकरण के तथ्य पर निर्णय लेना उचित नहीं है।77.

कानून-दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-गुजरात मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003-की व्याख्या:जब कोई अधिनियम दो अलग-अलग अभिव्यक्तियों का उपयोग करता है, तो उन्हें एक ही अर्थ के रूप में नहीं माना जा सकता है-इंद्रधनुष पत्र मामले पर निर्भरता अपीलार्थी के लिए कोई लाभ नहीं है और उस निर्णय को अपने स्वयं के तथ्यों तक ही सीमित रखा जाना है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

ग

पकड़ना:1.1 इसलिए जलप्रपात तंत्र के तहत वरीयताओं के पदानुक्रम में इंगित दावों की प्राथमिकता है:सबसे पहले, दिवाला समाधान प्रक्रिया की लागत और परिसमापन लागत; दूसरा, परिसमापन शुरू होने की तारीख से पहले 24 महीने की अवधि के लिए श्रमिकों का बकाया और ऐसे सुरक्षित लेनदार द्वारा प्रतिभूति छोड़ने की स्थिति में किसी सुरक्षित लेनदार को देय ऋण; तीसरा, परिसमापन शुरू होने की तारीख से पहले 12 महीने की अवधि के लिए श्रमिकों के अलावा अन्य कर्मचारियों को मजदूरी और कोई भी अवैतनिक बकाया; चौथा, असुरक्षित लेनदारों को देय वित्तीय ऋण; पांचवां, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को देय कोई भी राशि और प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन के बाद किसी भी राशि के लिए एक सुरक्षित लेनदार को देय ऋण; छठा, कोई भी शेष ऋण और बकाया; सातवां, प्राथमिकता शेयरधारक; और आठवां इक्विटी शेयरधारक या भागीदार। यह पदानुक्रम या प्राथमिकता का क्रम इस प्रकार सरकारी ऋणों [खंड (ई)] और परिचालन ऋणों [खंड (एफ)] को असुरक्षित वित्तीय लेनदारों के बकाया की तुलना में कम प्राथमिकता देता है।एक सुरक्षित लेनदार को देय ऋण, जब भी ऐसे सुरक्षित लेनदार ने धारा 52 में निर्धारित तरीके से प्रतिभूति छोड़ दी है, तो काफी उच्च प्राथमिकता प्राप्त होती है (दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत के तुरंत बाद), जबकि अन्य मामलों में, यानी जब सुरक्षित लेनदार प्रतिभूति नहीं छोड़ता है, तो दावे की प्राथमिकता कम होती है [धारा 53 (1) (ई) (ii)] "प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन के बाद किसी भी अवैतनिक राशि" के

संबंध में। एक अन्य विशेषता यह है कि सरकार को देय राशियों (अर्थात्, भारत की संचित निधि या किसी राज्य की संचित निधि में देय) को उसी तरीके से क्रमबद्ध किया जाता है जैसे सुरक्षित ऋणदाताओं को किया जाता है।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

1225

पास्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड v. रमन आई. एस. पी. ए. टी. प्राइवेट लिमिटेड और ओ. आर. एस.

जो अपने प्रतिभूति हित को नहीं छोड़ते हैं [धारा 53 (1) (ई) (ii)]। [पैरा 27 और 28] [1244-सी-जी]

1.2 धारा 52 सुरक्षित लेनदारों को परिसमापन प्रक्रिया (वह प्रक्रिया जिसके लिए परिसमापन विनियमों के विनियम 21 और 21 ए में निर्धारित किया गया है) में या तो अपने प्रतिभूति हित को छोड़ने या इसे लागू करने के लिए आगे बढ़ने का विकल्प देती है। बाद के विकल्प के मामले में, सुरक्षित लेनदार को पहले निर्धारित समय के भीतर (30 दिन, परिसमापन विनियमों की अनुसूची II के फॉर्म सी या डी में) अपना विकल्प इंगित करना होगा। परिसमापक तब, धारा 52 (3) के अनुसार, प्रतिभूत लेनदार को प्रतिभूति ऋण के रूप में ऐसे बकाया का भुगतान करने की अनुमति दे सकता है जो मौजूद साबित होते हैं। परिसमापक द्वारा मंजूरी मिलने पर, सुरक्षित लेनदार धारा 52 (4) के तहत अपने दावे को लागू करने के लिए आगे बढ़ सकता है। यदि प्रक्रिया के दौरान प्रतिरोध होता है, तो सुरक्षित लेनदार एन. सी. एल. टी. [धारा 52 (5) और (6)] से संपर्क कर सकता है। प्रवर्तन पर, प्राप्त की गई किसी भी अतिरिक्त राशि को परिसमापक [धारा 52 (7)] को दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि एक सुरक्षित लेनदार को परिसमापन प्रक्रिया की शुरुआत में, अपने सुरक्षित ब्याज को छोड़ना है या नहीं, इस बारे में एक सोचा-समझा निर्णय लेना पड़ता है। यदि यह ऐसा करता है, तो झरना तंत्र में इसका बकाया अधिक होता है। यदि वह अपने प्रतिभूति हित को न छोड़ने का विकल्प चुनता है, और इसके बजाय सफलता के बिना इसे लागू करने के लिए आगे बढ़ता है या प्रवर्तन की प्रक्रिया में अपने सभी बकाया का भुगतान करने में असमर्थ होता है, तो तब बलपूर्वक प्राथमिकता कम हो जाती है, और परिसमापक द्वारा परिसमापन संपत्ति की प्राप्ति पर परिसंपत्तियों के वितरण की प्रतीक्षा की जाती है। इस प्रकार परिकल्पित प्रक्रिया, एक सुरक्षित लेनदार के बकाया की वसूली के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाती है। यदि वे सुरक्षा छोड़ने का विकल्प चुनते हैं, तो उनकी प्राथमिकता उच्च श्रेणी की होती है; यदि वे ऐसी सुरक्षा को लागू करना चाहते हैं, तो परिसमापक द्वारा सूचना और सत्यापन के अधीन, वे ऐसा करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। कम गिरावट की स्थिति में, वे प्राथमिकता में कम स्थान पर होते हैं। यह कारण प्रतीत होता है, जैसा कि 2018 में संसदीय बहसों के परिणामस्वरूप टिप्पणियों के जवाब में दिए गए स्पष्टीकरण से स्पष्ट है, कि सुरक्षित लेनदारों ने अपने सुरक्षा हित को नहीं छोड़ने का विकल्प चुना है "यह माना जाता है कि ऐसे सुरक्षित लेनदारों ने परिसमापन कार्यवाही के बाहर अपनी सुरक्षा को लागू करके अपने अधिकांश बकाया की वसूली की है।" 27 इसमें ठोस तर्क है, क्योंकि जो लोग 'अलग दिखने' का विकल्प चुनते हैं और सुरक्षा हितों को लागू करते हैं, वे हैं

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

1226 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

क.

ऐसा करने की अनुमति; अतिरिक्त वसूली की स्थिति में, उन्हें परिसमापन कार्यवाही में वितरण के लिए इस तरह की अतिरिक्त राशि को सूचित करना होगा और सौंपना होगा; यदि वे अपने बकाया की वसूली करने में असमर्थ हैं, तो ऐसे सुरक्षित लेनदारों को निम्न श्रेणी में रखा जाता है। आई. बी. सी. के प्रावधानों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है, और सुरक्षित लेनदारों को विकल्प दिए जाते हैं, और परिसमापन कार्यवाही में अन्य लेनदारों के साथ उनके हितों को संतुलित किया जाता है। [पारस 34-38] [1249-F-G; 1250-A-F; 1251-A-B; 1256-B]

मोजर बेयर करमचारी यूनियन थ.अध्यक्ष महेश चंद शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य। (2023) एससीसी

ऑनलाइन एससी 547-संदर्भित।

ग

1.3 2003 के अधिनियम की धारा **56** के आधार पर, किसी भी व्यक्ति की "बिजली के लिए किसी भी शुल्क या बिजली के लिए शुल्क के अलावा किसी अन्य राशि का भुगतान करने में लापरवाही की स्थिति में" उसे बिजली की आपूर्ति, संचरण या वितरण या पहियों के संबंध में "देय" (पंद्रह दिनों के स्पष्ट 'लिखित नोटिस के बाद) "और ऐसे शुल्क या अन्य राशि की वसूली के अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना", एक लाइसेंसधारी (पी. वी. वी. एन. एल. जैसे वितरण लाइसेंसधारी सहित) को ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति को बिजली की आपूर्ति बंद करने का अधिकार है। **2003** के अधिनियम की धारा **181 (2) (x)** के आधार पर, राज्य आयोगों को विनियम बनाने का अधिकार है। धारा **50** राज्य आयोगों को बिजली शुल्क की वसूली, बिजली शुल्क के बिलिंग के लिए अंतराल, भुगतान न करने पर बिजली की आपूर्ति को काटने आदि के लिए "बिजली आपूर्ति संहिता" तैयार करने का अधिकार देती है। **2003** के अधिनियम और संबंधित संहिताओं के ये प्रावधान **2003** के अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार के लाइसेंसधारियों द्वारा बकाया की वसूली के लिए कानूनी ढांचा बनाते हैं। वर्तमान मामले में उत्तर प्रदेश राज्य आयोग ने **2005** की आपूर्ति संहिता तैयार की थी। **2005** की संहिता का खंड **6.15** अधिनियमित करता है कि बकाया की वसूली उत्तर प्रदेश सरकार विद्युत उपक्रम (देय वसूली) अधिनियम, **1958** के प्रावधानों के अनुसार होगी। [पारस 39-41] [1256-B-G]

डी.

ई.

च

जी.

1.4 के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड के मामले में इस अदालत के हाल के एक फैसले में उन परिस्थितियों की जांच की गई जिसमें इस तरह के 'आरोप' को कानून में गठित किया जा सकता है। इस अदालत ने माना कि आरोप का निर्माण आवश्यक रूप से **2003** के अधिनियम या पूर्ण विधान के एक स्पष्ट प्रावधान पर आधारित नहीं होना चाहिए, लेकिन ए हो सकता है

एच.

1227

पास्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड v. रमन आई. एस. पी. ए. टी. प्राइवेट लिमिटेड और ओ. आर. एस.

मूल कानून के तहत अधिकृत उचित रूप से बनाए गए नियमों द्वारा बनाया गया। इन परिस्थितियों में, पी. वी. वी. एन. एल. का यह तर्क कि आपूर्ति संहिता के खंड **4.3 (च) (iv)** के आधार पर, पक्षों के बीच समझौते में शर्तों के साथ पढ़ा जाता है,

निगमित देनदार की परिसंपत्तियों पर शुल्क लगाया गया था, योग्य है। एन. सी. एल. टी. के विवादित आदेश को सावधानीपूर्वक पढ़ने से यह भी पता चलता है कि इस स्थिति को स्वीकार कर लिया गया था। यह एन. सी. एल. ए. टी. के आदेश से स्पष्ट है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि पी. वी. वी. एन. एल. भी कानून के अनुसार 'सुरक्षित परिचालन लेनदार' की परिभाषा के तहत आता है। यह निष्कर्ष विचलित नहीं हुआ था, बल्कि विवादित आदेश द्वारा पुष्टि की गई थी। इन परिस्थितियों में, इस निष्कर्ष पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि पी. वी. वी. एन. एल. एक सुरक्षित लेनदार है। [पारस **42,43**] [**1258-ए-सी**]

ग

के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड **2023** एससीसी

ऑनलाइन एससी **603**-पर भरोसा किया गया।

1.4 परिसमापक के वकील ने प्रस्तुत किया था कि पी. वी. वी. एन. एल. का बकाया तकनीकी रूप से "सरकार" का बकाया था, और इस प्रकार मंजूरी की प्राथमिकता के क्रम में एक निचले स्थान पर था। अभिव्यक्ति "सरकारी बकाया" आई. बी. सी. में परिभाषित नहीं है-यह केवल प्रस्तावना में जगह पाता है। हालांकि, इस तरह के बकाया का गठन धारा **53 (1) (ई)** के तहत 'झरना तंत्र' में किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ कहा गया है कि, "केंद्र सरकार और राज्य सरकार को देय कोई भी राशि, जिसमें भारत की संचित निधि और राज्य की संचित निधि के रूप में प्राप्त होने वाली राशि भी शामिल है, धारा **53 (1)** के खंड (ए) से (डी) में वर्णित लेनदारों के वर्ग की प्राथमिकता में कम है। इस प्रकार, अन्य लेनदारों के अलावा एक वर्ग के रूप में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बकाया की एक अलग गणना या विनिर्देश मौजूद है, जिसमें ऐसे लेनदार भी शामिल हैं जिनके पास सुरक्षित ब्याज हो सकता है (जिसके संबंध में राशि उन्हें देय हो सकती है)। आई. बी. सी. के अधिनियमन से पहले की विभिन्न रिपोर्टों में सांविधिक कर, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार को देय अन्य बकाया राशि, या किसी भी सरकार के लिए संचित निधि में देय राशियों के कारण सरकार को ऋणों की प्राथमिकता को कम करने का बार-बार उल्लेख करने का अर्थ है कि ये बकाया अलग हैं और इन्हें सुरक्षित लेनदारों को देय राशि से अलग माना जाना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सामान्य खंड अधिनियम, **1897** द्वारा परिभाषित किया गया है। द.

डी.

ई.

च

जी.

एच.

1228 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

क.

पूर्व को धारा **3 (8), 32** और बाद वाले को धारा **3 (60)** द्वारा परिभाषित किया गया है। [पैरा **44**] [**1258-डी-जी**]

श्रीकांत बनाम वसंतराव और अन्य। [**2006**] **1** एससीआर **496** -

संदर्भित किया गया।

1.5 लेनदारों के अन्य वर्ग का विशिष्ट उल्लेख, जिनके बकाया वैधानिक हैं, जैसे कि कर्मचारियों या कर्मचारियों को देय बकाया, "भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान निधि" धारा **36 (4)** के तहत, जो इन गणना की गई राशियों को परिसमापन से बाहर करता है, विशेष रूप से स्पष्ट करता है कि कानून के तहत बकाया सभी बकाया को "सरकारी" बकाया के रूप में नहीं माना जाता है। दूसरे शब्दों में, सांविधिक निगमों को देय देय राशि जो "केंद्र या राज्य सरकार को देय राशि" के विवरण के भीतर नहीं आती है, जैसे कि उदाहरण के लिए उन कानूनों द्वारा बनाए गए निगमों को देय राशि जिनके पास अलग-अलग न्यायिक इकाई है, लेकिन जिनके बकाया देय सरकारी बकाया नहीं हैं या जो संबंधित समेकित निधियों में देय हैं, वे एक अलग आधार पर हैं। ऐसे निगम परिचालन लेनदार या वित्तीय लेनदार या सुरक्षित लेनदार हो सकते हैं जो उनके द्वारा निगमित देनदार के साथ किए गए लेनदेन की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरी ओर, देय या कोषागार में जमा किए जाने की आवश्यकता, जैसे कर, शुल्क,

आदि जो मोटे तौर पर संविधान के अनुच्छेद **265** के दायरे में आते हैं, 'सरकारी बकाया' हैं और इसलिए आई. बी. सी. की धारा **53 (1) (एफ)** के अंतर्गत आते हैं। पी. वी. वी. एन. एल. की निस्संदेह सरकारी भागीदारी है। हालाँकि, यह इसे सरकार या 'राज्य सरकार' का हिस्सा नहीं बनाता है। इसके कार्यों को अन्य संस्थाओं, निजी और सार्वजनिक दोनों द्वारा दोहराया जा सकता है। बिजली की आपूर्ति, उत्पादन, पारेषण और बिजली के वितरण को **2003** के अधिनियम के संदर्भ में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर उदार बनाया गया है। निजी संस्थाओं को लाइसेंस रखने का अधिकार है। इस संदर्भ में, इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि वितरण लाइसेंसधारियों के रूप में निजी भागीदारी काफी व्यापक है। इन कारणों से, यह माना जाता है कि वर्तमान मामले में, पी. वी. वी. एन. एल. को देय बकाया या देय राशि आई. बी. सी. की धारा **53 (1) (एफ)** के विवरण के भीतर नहीं आती है। [पारस **46,47**] [**1261-बी-जी**]

ग

डी.

ई.

च

जी.

दम दम नगर पालिका के नगर आयुक्त और अन्य बनाम भारतीय पर्यटन विकास निगम और अन्य। 1995 में

(5) एससीसी 251:[1995] 2 पूरक। एस. सी. आर. 433-पर निर्भर।

एच.

1229

पास्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड v. रमन आई. एस. पी. ए. टी. प्राइवेट लिमिटेड और ओ. आर. एस.

क.

1.6 धारा **53** विभिन्न वर्गों के लेनदारों के दावों के पदानुक्रम या प्राथमिकता प्रदान करने वाले जलप्रपात तंत्र को अधिनियमित करती है। धारा **53** की सावधानीपूर्वक अभिकल्पना परिसमापन कार्यवाही के दौरान परिसमापक की देय लागतों और खर्चों के बाद, दूसरे स्थान पर सुरक्षित लेनदारों और श्रमिकों को देय राशियों का पता लगाती है। हालाँकि, सरकार को देय देय राशि सुरक्षित लेनदारों और यहां तक कि असुरक्षित और परिचालन लेनदारों से बहुत कम है। इस डिजाइन को या तो इंद्रधनुष पत्रों में अदालत के ध्यान में नहीं लाया गया था या पूरी तरह से छूट गया था। किसी भी स्थिति में, निर्णय में आई. बी. सी. के उन प्रावधानों पर ध्यान नहीं दिया गया है जो केंद्र या राज्य सरकार को देय बकाया की तुलना में सुरक्षित लेनदारों को देय बकाया को उच्च स्तर पर मानते हैं। गुजरात मूल्य वर्धित कर अधिनियम, **2003** निस्संदेह देय और देय या बकाया राशि के संबंध में एक शुल्क बनाता है। (वर्तमान मामले में, धारा **53 (1) (ई)** में सरकारी बकाया की एक विशिष्ट गणना के अभाव में) यह अभिनिर्धारित करना संभव होगा कि राज्य को 'सुरक्षित लेनदार' के रूप में माना जाना है। हालाँकि, एक ओर सुरक्षित लेनदार को देय राशि का अलग और विशिष्ट व्यवहार और दूसरी ओर सरकार को देय बकाया स्पष्ट रूप से संसद के इरादे को दर्शाता है कि बाद वाले के साथ अलग व्यवहार किया जाए-और वर्तमान मामले में, कम प्राथमिकता दी जाए। यह इरादा अधिनियम की प्रस्तावना को पढ़ने से भी स्पष्ट होता है। जब कोई अधिनियम दो अलग-अलग अभिव्यक्तियों का उपयोग करता है, तो उन्हें एक ही अर्थ के रूप में नहीं माना जा सकता है। [पारस **49-51**] [**1262-G-H; 1263-A-E**]

ग

डी.

ई.

राज्य कर अधिकारी बनाम रेनबो पेपर्स लिमिटेड [**2022**] **13** एससीआर

च

बृहन्मुंबई महानगर पालिका और अन्न बनामविलिंगटन

स्पोर्ट्स क्लब और ओआरएस। [2013] 16 एस. सी. आर. 216-संदर्भित।

1.7 आई. बी. सी. की धारा **238** बिजली अधिनियम, **2003** के प्रावधानों को दरकिनार करती है, इसके बावजूद कि इसमें दो विशिष्ट प्रावधान हैं जो गैर-अबाधित खंडों (यानी धारा **173** और **174**) के साथ खुलते हैं। [पैरा **52**] [1263-एफ-जी]

जी.

सुंदरेश भट्ट, ए. बी. जी. शिपयार्ड के परिसमापक बनाम केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड **2022** एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. **1101**; डंकन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम एजे एग्रीकेम (**2019**)

9 एससीसी **725**: [2019] **12** एससीआर **830**-पर निर्भर था।

एच.

1230 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

क.

इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक और ए. एन. आर. [2017] **8** एससीआर **33**; सीआईटी बनाम मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड (**2018**) **18** एससीसी **786**; घनश्याम मिश्रा एंड संस (पी) लिमिटेड बनाम। एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड [2021] **13** एससीआर **737**; जगमोहन बजाज बनाम शिवम फ्रेग्रेस प्राइवेट

लिमिटेड **2018** एस. सी. सी. ऑनलाइन एन. सी. एल. ए. टी. **413**-संदर्भित। **1.8** धारा **78** में कहा गया है कि जब कोई कंपनी जिसकी संपत्ति शुल्क के अधीन है, उसे पंजीकृत करने में विफल रहती है, तो शुल्क धारक (या कंपनी की संपत्तियों पर शुल्क का हकदार व्यक्ति) इसका पंजीकरण करा सकता है। आई. बी. सी. की धारा **3 (31)** "सुरक्षा हित" को व्यापक रूप से परिभाषित करती है। इस अदालत की राय में, परिसमापक इस स्तर पर इस पहलू का आग्रह नहीं कर सकता है, क्योंकि एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के समवर्ती निष्कर्षों के अनुसार पी. वी. वी. एन. एल. एक सुरक्षित लेनदार है। [पैरा **55**] [1266-ई]

ग

न्यासी मंडल, पोर्ट ऑफ मुंबई बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन [1998] 2 एस. सी. आर. **774**; जितेंद्र नाथ सिंह बनाम आधिकारिक परिसमापक और अन्य। [2012] **13** एससीआर **339**; आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड बनाम सिडको लेदर लिमिटेड. [2006] सप्लीमेंट **1** एससीआर **528**; जलगांव जनता शकारी बैंक लिमिटेड बनाम बिक्री कर के संयुक्त आयुक्त, नोडल **9**, मुंबई और एएनआर।

डी.

2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम **1767**; पश्चिम बंगाल राज्य

विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनाम श्री वासवी

ई.

इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ए. एन. आर. **2022** एससीसी ऑनलाइन कैल **1918**;

भारत संघ और अन्य बनाम शाह गोवर्धन एल. काबरा

शिक्षक महाविद्यालय [2002] पूरक 3 एससीआर 220; यूको बैंक

& एन. आर. वी.दीपक देबबर्मा और अन्य। [2016] 11 एस. सी. आर. 723; स्विस् रिबन (पी) लिमिटेड बनाम.भारत संघ **(2019) 4 एससीसी 17:[2019] 3 एस. सी. आर. 535;** के. शशिधर बनाम इंडियन ओवरसीज बैंक **[2019] 3 एस. सी. आर. 845;** एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के लेनदारों की समिति बनाम सतीश कुमार गुप्ता और अन्य। **[2019] 16 एस. सी. आर. 275;** सदस्य, राजस्व बोर्ड बनाम एंथनी पॉल

च

बेंथल [1955] 2 एस. सी. आर. 842-संदर्भित।

दिवालियापन कानून सुधार समिति की रिपोर्ट, (2015), शीर्षक 5.5।8- परिसमापन में भुगतान की प्राथमिकता स्थापित करना; दिवाला विधि समिति की रिपोर्ट

जी.

(2020)- शीर्षक 7.3-किसी सुरक्षित लेनदार द्वारा प्रतिभूति ब्याज की प्राप्ति या त्याग **(पृष्ठ। 76)-संदर्भित।**

एच.

1231

पास्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड v.रमन आई. एस. पी. ए. टी. प्राइवेट लिमिटेड और ओ. आर. एस.

क.

निर्णीत विधि संदर्भ

[1998] 2 एससीआर 774

संदर्भित किया गया है

पैरा **7 [2022] 13 एस. सी. आर. 808** विशिष्ट पैरा **9 [2012] 13 एस. सी. आर. 339** निर्दिष्ट

पैरा **15 [2006]** सप्लीमेंट **1 एससीआर 528** पैरा **15 [2002]** सप्लीमेंट **3 एससीआर 220** पैरा **18 [2016] 11 एससीआर 723** को संदर्भित किया गया है

पैरा **18**

[2017] 8 एससीआर 33

संदर्भित किया गया है

पैरा **18**

ग

[2019] 3 एससीआर 535

संदर्भित किया गया है

पैरा **18**

पैरा **22**

संदर्भित किया गया है

[2019] 3 एससीआर 845

[2019] 16 एससीआर 275

संदर्भित किया गया है

पैरा 22

[2006] 1 एससीआर 496

संदर्भित किया गया है

पैरा 44

[1995] 2 पूरक।एस. सी. आर. 433 पर निर्भर

पैरा 45

डी.

पैरा 51

संदर्भित किया गया है

[1955] 2 एससीआर 842

[2013] 16 एससीआर 216

संदर्भित किया गया है

पैरा 51

[2019] 12 एससीआर 830

पर भरोसा किया

पैरा 52

(2018) 18 एस. सी. सी. 786

संदर्भित किया गया है

पैरा 52

ई.

[2021] 13 एससीआर 737

संदर्भित किया गया है

पैरा 52

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2019 की सिविल अपील संख्या 7976।

2018 के सी. ए. ए. टी. सं. 639 में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण के दिनांक 15.05.2019 के निर्णय और आदेश से।

च

प्रदीप मिश्रा, दिलीप ध्यानी, भुवन एनचंद, सूरज सिंह, मनोज कुमार शर्मा, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

अरविंद कुमार गुप्ता, सुश्री हिना जॉर्ज, सुश्री शिवानी शर्मा, सुश्री पूर्ति गुप्ता, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

जी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. रवींद्र भाट, जे.

1. अपीलार्थी पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (इसके बाद, "पी. वी. वी. एन. एल".) राष्ट्रीय प्राधिकरण के एक आदेश से व्यथित है।

एच.

1232

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

क.

कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (इसके बाद, "एन. सी. एल. ए. टी".) 1 जिसने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, इलाहाबाद (इसके बाद, "एन. सी. एल. टी"./"न्यायनिर्णायक प्राधिकरण") के एक आदेश के खिलाफ अपनी अपील को खारिज कर दिया, 2 जिसने जिला मजिस्ट्रेट और तहसीलदार, मुजफ्फरनगर को प्रतिवादी रमन इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद, "कॉर्पोरेट देनदार") की परिसमापक के पक्ष में संपत्ति (जो पहले अपीलकर्ता के अनुरोध पर संलग्न की गई थी) को तुरंत जारी करने का निर्देश देने वाले एक आवेदन की अनुमति दी।

आई. एफ. एक्टस

ग

2. दोनों पक्षों ने बिजली की आपूर्ति के लिए 11.02.2010 पर एक समझौता किया था। समझौते के खंड 5 में प्रावधान किया गया है कि:

“ बकाया राशि कंपनी की परिसंपत्तियों पर शुल्क होगी। बिक्री से पहले, बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा और समझौतों/बिक्री के लिए विलेख में विशेष रूप से बकाया राशि और उसके भुगतान की विधि का उल्लेख किया जाएगा।”

डी.

3. पी. वी. वी. एन. एल. समय-समय पर निगमित देनदार को बिजली की आपूर्ति के लिए बिल उठाता था। चूंकि बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए पी. वी. वी. एन. एल. ने आदेश संख्या 1048, दिनांक 12.01.2016 द्वारा निगमित देनदार की संपत्तियों को कुर्क कर लिया। तहसीलदार, मुजफ्फरनगर ने आदेश संख्या 1423 एफ दिनांक 23.01.2016 द्वारा बिक्री, दान या किसी अन्य तरीके से संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक लगा दी और संपत्तियों पर शुल्क भी लगाया। निगमित देनदार ने शुरू में आई. बी. सी. के तहत समाधान प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, हालांकि वह प्रक्रिया सफल नहीं रही। इसलिए यह परिसमापन के अधीन हो गया।

ई.

च

4. अंतिम बिल दिनांक 27.01.2017 के तहत, कुल बकाया 4,32,33,883/- था। इसमें से जिला कलेक्टर ने खसरा नं. 0.4710 पर स्थित चल और अचल संपत्तियों की नीलामी द्वारा 05.03.2018 पर 2,50,14,080/- के बकाया की वसूली के लिए नोटिस जारी किया। परिसमापक ने आरोप लगाया कि जब तक जिला कलेक्टर, मुजफ्फरनगर और तहसीलदार, मुजफ्फरनगर के कुर्की आदेशों को एन. सी. एल. टी. द्वारा दरकिनार नहीं किया जाता है, तब तक कोई भी खरीदार परिसमापक

के संपत्ति बेचने के अधिकार के बारे में अनिश्चितता के कारण कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति नहीं खरीदेगा। परिसमापक ने यह भी दलील दी कि पी. वी. वी. एन. एल. का दावा होगा

रू

जी.

1 2018 की कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) सं. 639, दिनांक 15.05.2019। 2 सी. पी. सं. में सी. ए. सं. 88/ए. एल. डी./2018। (आईबी) 23/एएलडी/2017, दिनांक 21.08.2018।

एच.

1233

पास्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड v. रमन आई. एस. पी. ए. टी. प्राइवेट लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

क.

आई. बी. सी. की धारा 53 के तहत निर्धारित प्राथमिकता के क्रम में वर्गीकृत किया जाएगा, और पी. वी. वी. एन. एल. परिसमापन परिसंपत्तियों की बिक्री से अन्य सुरक्षित लेनदारों के साथ आय के आनुपातिक वितरण का हकदार होगा।

5. परिसमापक की स्थिति ने अंततः एन. सी. एल. ए. टी. को जिला मजिस्ट्रेट और तहसीलदार, मुजफ्फरनगर को जब्त की गई संपत्ति को तुरंत उसके पक्ष में जारी करने का निर्देश दिया ताकि संपत्ति की बिक्री को सक्षम बनाया जा सके, और संपत्ति के मूल्य की प्राप्ति के बाद, आई. बी. सी. के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार इसका वितरण सुनिश्चित किया जा सके। एन. सी. एल. ए. टी. ने एन. सी. एल. टी. के इस तर्क का भी समर्थन किया कि पी. वी. वी. एन. एल. 'परिचालन लेनदार' की परिभाषा के भीतर आता है, जो कानून के अनुसार परिसमापन प्रक्रिया में अपने बकाया का भुगतान कर सकता है।

ग

II. पी. वी. वी. एन. एल. एस. ए. आर. जी. यू. एम. एन. एस.

6. पी. वी. वी. एन. एल. के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप मिश्रा ने प्रस्तुत किया कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 173 और 174 (इसके बाद, "2003 अधिनियम") का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986; परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962; और रेलवे अधिनियम, 1989 को छोड़कर अन्य सभी कानूनों पर प्रबल प्रभाव पड़ा। बिजली के सभी पहलुओं से संबंधित एक विशेष कानून होने के नाते-उत्पादन, संचरण, वितरण और विवादों के निर्णय-आई. बी. सी. सहित अन्य सभी कानूनों पर इसकी प्रधानता थी, जो कि बहुत बाद में लागू कॉर्पोरेट दिवालियापन से संबंधित एक 'सामान्य' कानून था। 2003 के अधिनियम और उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 (इसके बाद, "2005 संहिता") सहित इसके तहत बनाए गए विनियमों के संदर्भ में, बिजली बकाया की वसूली के लिए एक विशेष तंत्र मौजूद था। इसलिए, पी. वी. वी. एन. एल. जैसे बिजली आपूर्तिकर्ताओं के अधिकार अधीनस्थ नहीं थे और आई. बी. सी. के तहत 'दावों की प्राथमिकता' तंत्र के अधीन थे। इसलिए, पी. वी. वी. एन. एल. स्वतंत्र रूप से परिसमापन प्रक्रिया से बाहर रहने और अपने बकाया की वसूली करने का विकल्प चुन सकती है।

डी.

ई.

च

7. विद्वान वकील ने बोर्ड में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया

न्यासी, पोर्ट ऑफ मुंबई बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, 3 जिसमें यह

अदालत ने फैसला सुनाया था कि प्रमुख बंदरगाह न्यास अधिनियम, 1963 के तहत बंदरगाह बकाया, परिसमापन कार्यवाही में सुरक्षित लेनदारों सहित अन्य सभी दावों को खारिज कर देता है। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि आई. बी. सी. की धारा 238

2003 के अधिनियम की धारा 173 और 174 को ओवरराइड नहीं कर सकती है, क्योंकि बाद वाला (यानी बिजली अधिनियम) एक विशेष अधिनियम है, और आई. बी. सी. पर प्रबल होगा, जो बाद में एक सामान्य कानून है, जो दिवालियापन से संबंधित है।

जी.

8. वकील ने आग्रह किया कि 2003 के अधिनियम (धारा 42,45 और 56) और 2005 की संहिता (खंड 4.3 और 6.15) के प्रावधानों में

एच.

3 न्यासी मंडल, पोर्ट ऑफ मुंबई बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, 1998 (2) एससीआर 774।

1234

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

बिजली शुल्क की वसूली के लिए तंत्र। 2003 का अधिनियम एक गैर-अस्थायी खंड के साथ एक 'विशेष अधिनियम' होने के कारण, 'सामान्य' आई. बी. सी. कानून पर एक प्रबल प्रभाव पड़ेगा। बिजली बकाया की तेजी से वसूली के लिए इस तंत्र को पूरी तरह से लागू करना पड़ा। इस प्रकार, आई. बी. सी. के प्रावधान और परिसमापन कार्यवाही में इसके तहत दावों की प्राथमिकता अलग थी और 2003 के अधिनियम और 2005 संहिता के तहत बिजली बकाया की वसूली की अनुमति के बाद वितरण के लिए उपलब्ध अन्य राशियों के संबंध में लागू की गई थी।

9. विद्वान वकील ने भी इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया

राज्य कर अधिकारी बनाम रेनबो पेपर्स लिमिटेड, 4 जिसमें इस अदालत ने निर्णय दिया

कि गुजरात मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 के तहत कर दावों के लिए सरकार के पक्ष में बनाए गए प्रतिभूति हित के आधार पर, कर प्राधिकरण यानी सरकार, आई. बी. सी. के तहत एक सुरक्षित लेनदार थी। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि किसी समाधान योजना में सरकार को देय ऐसे कर या वैधानिक बकाया को शामिल नहीं किया जाता है, तो यह आई. बी. सी. के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होगा और इस प्रकार, राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं होगा।

ग

डी.

10. वैकल्पिक रूप से, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि बिजली बकाया भी बिजली सेवा प्रदाताओं के पक्ष में 'सुरक्षा हित' थे। उन्होंने 'सुरक्षित लेनदार' की परिभाषा पर भरोसा किया जिसका अर्थ था

“ एक लेनदार जिसके पक्ष में प्रतिभूति ब्याज बनाया जाता है।” 5 इस तरह

‘आई. बी. सी. के तहत सुरक्षा हित को इस प्रकार परिभाषित किया गया था:

ई.

“अधिकार, स्वामित्व या ब्याज या किसी संपत्ति में दावा, जो किसी लेन-देन द्वारा किसी सुरक्षित लेनदार के पक्ष में बनाया गया है, या उसके लिए प्रदान किया गया है, जो किसी दायित्व के भुगतान या प्रदर्शन को सुरक्षित करता है और जिसमें बंधक, शुल्क, परिकल्पना, समनुदेशन और बोझ या कोई अन्य समझौता या व्यवस्था शामिल है जो किसी भी व्यक्ति के किसी भी दायित्व के भुगतान या प्रदर्शन को सुरक्षित करता है।” 6

च

11. 'परिभाषा के संपत्ति खंड में दावा तब किया जा सकता है जब कोई कानून के तहत किसी भी दायित्व का भुगतान या प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त, "स्थानांतरण" शब्द को आई. बी. सी. के तहत परिभाषित किया गया था जिसका अर्थ है:

"इसमें बिक्री, खरीद, विनिमय, बंधक, गिरवी, उपहार, ऋण या अधिकार, स्वामित्व, अधिकार या ग्रहणाधिकार के हस्तांतरण का कोई अन्य रूप शामिल है।" 7

जी.

4 राज्य कर अधिकारी बनाम रेनबो पेपर्स लिमिटेड, 2022 (13) एससीआर 808।

5 धारा 3 (30), आई. बी. सी. 6 धारा 3 (31), आई. बी. सी. 7 धारा 3 (34), आई. बी. सी.

एच.

1235

पास्चिमंचाल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम. रमन आई. एस. पी. ए. टी. प्राइवेट लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

क.

12. यह आग्रह किया गया कि 'प्रतिभूति हित' और 'हस्तांतरण' की परिभाषाओं को पढ़ने से संकेत मिलता है कि आई. बी. सी. का इरादा 'प्रतिभूति हित' की अवधारणा में निगमित देनदार के खिलाफ कानून में उत्पन्न होने वाले वैधानिक दावों सहित सभी दावों को शामिल करना था। इस प्रकार, दायित्व और वैधानिक शुल्क भी 'सुरक्षा हित' थे।

III. एल इक्विडेटर एस ए आरगुमेन्ट्स

13. परिसमापक की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार गुप्ता ने तर्क दिया कि आई. बी. सी. के तहत लेनदारों को या तो सुरक्षित या असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसके अलावा, आई. बी. सी. का एक मुख्य आकर्षण वित्तीय और परिचालन ऋणदाताओं के बीच अंतर और वसूली के संबंध में उनका अंतर व्यवहार था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि दिवालियापन कानून सुधार समिति की रिपोर्ट, 2015 और दिवाला कानून पर UNCITRAL विधायी गाइड, यह निर्धारित करती है कि IBC के तहत सरकारी बकाया को प्राथमिकता नहीं दी गई थी। यह कानून की पृष्ठभूमि बनी। वास्तव में, आई. बी. सी. के उद्देश्यों और कारणों का विवरण सरकारी बकाया के भुगतान की प्राथमिकता में परिवर्तन को निर्धारित करता है।

ग

डी.

14. यह तर्क दिया गया कि धारा 52 (3) के संदर्भ में, सुरक्षित लेनदारों द्वारा प्रतिभूति ब्याज की प्राप्ति से पहले, परिसमापक को एक सूचना उपयोगिता द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड से या ऐसे अन्य माध्यमों से प्रतिभूति ब्याज के अस्तित्व को सत्यापित करना था जो भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (इसके बाद, "बोर्ड/आईबीबीआई") द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।⁸ प्रतिभूति ब्याज का अस्तित्व एक सुरक्षित लेनदार द्वारा विनियमन 21, आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 (इसके बाद, "परिसमापन विनियम") के संदर्भ में साबित किया जा सकता है।

ई.

15. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 77 (पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 125 के अनुरूप) के तहत किसी भी आरोप का पंजीकरण अनिवार्य था। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (इसके बाद, "टी. पी. ए.") की धारा 48 अधिकारों की प्राथमिकता से संबंधित है, और परिसमापन कार्यवाही में परिसंपत्तियों के वितरण में लेनदारों के बीच अंतर-प्राथमिकताएं प्रबल हैं। वकील ने जितेंद्र नाथ के इस अदालत के फैसलों का उल्लेख किया

च

जी.

सिंह बनाम आधिकारिक परिसमापक और अन्य। 9 और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड बनाम.सिडको लेदर लिमिटेड 10
8 भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड की स्थापना आई. बी. सी. की धारा 188 के तहत की गई है। धारा 196 के तहत
शक्तियों की गणना की गई है।

9 जितेंद्र नाथ सिंह बनाम आधिकारिक परिसमापक और अन्य।, 2012 (13) एससीआर 339। 10 आई. सी. आई. सी.
आई. बैंक लिमिटेड बनामसिडको लेदर लिमिटेड, 2006 पूरक (1) एस. सी. आर. 528

एच.

1236

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

16. यह प्रस्तुत किया गया था कि सरकारी बकाया आई. बी. सी. की धारा 53 (1) (ई) (आई) के तहत 'झरना तंत्र' में रखा
गया था। विद्वान वकील ने इस बात पर जोर दिया कि पुराने कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत भी, धारा 529 ए ने सुरक्षित
लेनदारों और श्रमिकों को देय ऋणों को प्राथमिकता प्रदान की, और धारा 530 ने धारा 529 ए में सन्निहित प्राथमिकता के
अधीन करों का भुगतान किया। इसी तरह, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 326 के तहत सुरक्षित लेनदारों और श्रमिकों
को देय ऋणों की प्राथमिकता परिलक्षित हुई। धारा 327 ने धारा 326 में सन्निहित प्राथमिकता के अधीन करों का भुगतान
किया। यह आग्रह किया गया कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके
बाद, "सरफेसी अधिनियम") की धारा 26 ई और बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993
(इसके बाद, "आर. डी. डी. बी. एफ. आई. अधिनियम") की धारा 31 बी में सुरक्षित लेनदारों को अन्य बकाया राशि पर
प्राथमिकता दी जाए। बंबई उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का फैसला

ग

जलगाँव जनता शकारी बैंक लिमिटेड बनाम. बिक्री के संयुक्त आयुक्त

कर, नोडल 9, मुंबई और अन्य, 11 ने सरफेसी अधिनियम की धारा 26 ई के तहत सुरक्षित लेनदारों को दी गई प्राथमिकता
को मजबूत किया।

डी.

17. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि बिजली बकाया को कोई प्राथमिकता नहीं है, और उच्च न्यायालय के फैसलों, विशेष रूप
से उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनाम श्री वासवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ए. एन.
आर. 12 यह था

प्रस्तुत किया कि एक कानून के तहत आरोप का निर्माण एक तथ्य की बात थी जिसे साबित करना था। वर्तमान मामले में, कानून
(2005 संहिता) ने केवल बिजली बकाया की वसूली को सक्षम किया जैसे कि वे राजस्व के बकाया की वसूली थी। इसके
परिणामस्वरूप अपीलार्थी के पक्ष में 'सुरक्षा हित' का सृजन नहीं हुआ। इसके अलावा, इस तरह का ब्याज परिसमापन विनियमों
और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 77 के अनुसार पंजीकृत नहीं किया गया था।

ई.

च

18. विद्वान वकील ने आग्रह किया कि दो प्रविष्टियों के बीच स्पष्ट रूप से अतिव्यापी होने के मामले में, कानून की वास्तविक प्रकृति और जिस प्रविष्टि के भीतर यह गिरता है, उसका पता लगाने के लिए 'पीठ और सार' के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए-भारत संघ के निर्णयों पर निर्भरता रखी गई थी

& ओआरएस. वी.शाह गोवर्धन एल. काबरा टीचर्स कॉलेज 13 और यूसीओ

जी.

11 जलगाँव जनता शकारी बैंक लिमिटेड बनाम.बिक्री कर के संयुक्त आयुक्त, नोडल 9,

मुंबई और एएनआर।, 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 1767।

12 पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनाम श्री वासवी इंडस्ट्रीज

लिमिटेड एंड ए. एन. आर., 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 1918

13 भारत संघ और अन्य बनामशाह गोवर्धन एल. काबरा टीचर्स कॉलेज, (2002)

एच.

(3) एससीआर 220।

1237

पाश्चिमंचाल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम.रमन आई. एस. पी. ए. टी. प्राइवेट लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

क.

बैंक एंड ए. एन. आर. वी.दीपक देबबर्मा और अन्य। 14.इसे ध्यान में रखते हुए

सिद्धांत रूप में, आई. बी. सी. इस प्रकार एक विशेष कानून था जो दिवाला, दिवालियापन और कंपनियों के समापन के पूरे विषय से संबंधित था।इसके प्रावधान 2003 के अधिनियम की तुलना में बाद के थे। 2003 के अधिनियम की धारा 173 और 174 के बावजूद, आई. बी. सी. की धारा 238 के आधार पर, आई. बी. सी. के प्रावधान प्रबल होंगे और इनका प्रबल प्रभाव होगा।यह प्रस्तुत किया गया कि आई. बी. सी. के तहत कानून अपनी स्थापना के बाद से लगातार विकसित हो रहा था।

2016. रिलायंस को इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम.आईसीआईसीआई बैंक एंड ए. एन. आर., 15 और स्विस रिबन (पी) लिमिटेड बनाम.भारत संघ 16 जो

आई. बी. सी. को बरकरार रखा और धारा 238 के आधार पर अधिनियम की प्रबल प्रकृति पर जोर दिया।

ग

IV. एक नैलिसिस

ए. एस. चैं ऑफ द आई. बी. सी.

19. आई. बी. सी. को वाणिज्यिक दिवालियापन पर कानूनी व्यवस्था को एकीकृत करने के उद्देश्य से लागू किया गया था।ऋण के पुनर्भुगतान में किसी निगमित देनदार के चूक करने पर 17, दिवाला समाधान प्रक्रिया तब शुरू की जा सकती है जब चूक का मूल्य वैधानिक सीमा (धारा 4) को पार कर जाता है; या इसे निगमित देनदार या वित्तीय लेनदार या परिचालन लेनदार (धारा 6) द्वारा शुरू किया जा सकता है।आई. बी. सी. इन दोनों वर्गों के लेनदारों के ऋणों के बीच अंतर करता है।एक वित्तीय लेनदार को धारा 5 (7) के तहत परिभाषित किया गया है, "एक व्यक्ति को

डी.

ई.

जिस पर वित्तीय ऋण बकाया है। "वित्तीय ऋण" को परिभाषित किया गया है -

धारा 5 (8) एक ऐसे ऋण के रूप में जो धन के समय मूल्य के लिए विचार के विरुद्ध वितरित किया जाता है। दूसरी ओर, एक परिचालन लेनदार वह होता है जिस पर परिचालन ऋण बकाया होता है। "धारा के तहत "परिचालन ऋण"

5(21) "वस्तुओं या सेवाओं के प्रावधान के संबंध में एक दावा" है।

च

20. आई. बी. सी. की धारा 7 और 8 क्रमशः वित्तीय लेनदारों और परिचालन लेनदारों द्वारा दिवालिया प्रक्रिया की शुरुआत को नियंत्रित करती है। निगमित देनदार एक निर्धारित समय अवधि के भीतर ऋण का मुकाबला कर सकता है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को सूचना उपयोगिता के अभिलेखों से या साक्ष्य के आधार पर चूक के अस्तित्व का निर्धारण करना होता है।

जी.

14 यूको बैंक और ए. एन. आर. बनाम दीपक देबबर्मा और अन्य, (2016) (11) एससीआर 723। 15 इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक और ए. एन. आर., (2017) 8 एससीआर 33. 16 स्विस् रिबन (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ (2019) 4 एस. सी. सी. 17.

17 धारा 3 (12) में चूक को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, "जब ऋण का भुगतान नहीं किया जाता है।

ऋण की राशि का पूरा या कोई हिस्सा या किश्त देय और देय हो गया है और ऋणी या कॉर्पोरेट ऋणी द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

18 धारा 3 (11) के अनुसार, जिसमें कहा गया है कि ऋण 'दावे' के संबंध में दायित्व का दायित्व है। एक 'दावा' को अन्य बातों के साथ-साथ धारा 3 (6) के तहत "भुगतान का अधिकार" के रूप में परिभाषित किया गया है।

एच.

1238

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

लेनदारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और इसे कॉर्पोरेट देनदार को सूचित किया जाता है-यह समाधान प्रक्रिया शुरू करता है, जिसे आवेदन (धारा 12) के प्रवेश की तारीख से 180 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, और 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए 180 दिनों से आगे बढ़ाया जा सकता है यदि लेनदारों की समिति (इसके बाद, "सीओसी") 75 प्रतिशत मतदान शेयरों के वोट से निर्णय लेती है। इस प्रकार त्वरित समाधान पूरी समाधान प्रक्रिया का मुख्य आधार है। आवेदन को स्वीकार करने पर, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा संहिता की धारा 14 के तहत एक स्थगन घोषित किया जाना है, जिसके बाद अंतरिम समाधान पेशेवर (इसके बाद, "आई. आर. पी.") के विवरण के साथ दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि का संकेत देने वाली एक सार्वजनिक घोषणा की जानी है। सी. ओ. सी. के निर्देशों पर एक चालू संस्था के रूप में निगमित देनदार का प्रबंधन आई. आर. पी. (और बाद में धारा 28 के तहत आर. पी. के तहत) में निहित है, जो धारा 17 के अनुसार आई. बी. सी. के अध्याय IV के तहत पंजीकृत एक प्रशिक्षित व्यक्ति है। सी. ओ. सी. के निर्णय वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के कम से कम 75 प्रतिशत के वोट से लिए जाते हैं। निगमित देनदार को वापस पटरी पर लाने का इच्छुक या इच्छुक कोई भी व्यक्ति, धारा 30 के तहत, आर. पी. को एक समाधान योजना प्रस्तुत कर सकता है, जो एक सूचना ज्ञापन के आधार पर तैयार की जाती है। जब ऐसी योजना को सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को उसी की संतुष्टि दर्ज करनी होती है-यह तब निगमित देनदार के साथ-साथ उसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों, गारंटर्स और अन्य हितधारकों के लिए बाध्यकारी हो जाता है। समाधान योजना के अनुमोदन के तुरंत बाद, धारा 14 के तहत प्राधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश का प्रभाव समाप्त हो जाता है।

ग

डी.

ई.

21. जब समाधान प्रक्रिया में कोई सफलता नहीं मिलती है, या कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है, और कुछ अन्य स्थितियों में, कॉर्पोरेट देनदार परिसमापन चरण में प्रवेश करता है। यह आई. बी. सी. की धारा 33 द्वारा प्रदान किया गया है, जिसे नीचे निकाला गया है:

च

“ धारा 33-परिसमापन की शुरुआत

(1) जहाँ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, -

जी.

(क) दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि की समाप्ति से पहले या धारा 12 के तहत निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अनुमत अधिकतम अवधि या धारा 56 के तहत फास्ट ट्रैक निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो, धारा 30 की उप-धारा (6) के तहत समाधान योजना प्राप्त नहीं करती है; या क

एच.

1239

पास्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड v. रमन आई. एस. पी. ए. टी. प्राइवेट लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

(ख) धारा 31 के तहत समाधान योजना को उसमें निर्दिष्ट आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन के लिए अस्वीकार कर देगा, यह-

(i) एक आदेश पारित करेगा जिसमें निगमित ऋणी को इस अध्याय में निर्धारित तरीके से समाप्त करने की आवश्यकता होगी;

((ii) एक सार्वजनिक घोषणा जारी करें जिसमें कहा गया हो कि निगमित देनदार परिसमापन में है; और

(iii) इस तरह के आदेश को उस प्राधिकरण को भेजे जाने की आवश्यकता है जिसके साथ निगमित देनदार पंजीकृत है।

(2) जहां समाधान पेशेवर, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय, लेकिन समाधान योजना की पुष्टि से पहले, लेनदारों की समिति के निर्णय के बारे में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को सूचित करता है। निगमित देनदार को परिसमापन करने के लिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण उप-धारा (1) के खंड (बी) के उपखंड (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट परिसमापन आदेश पारित करेगा। स्पष्टीकरण-इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लेनदारों की समिति धारा 21 की उप-धारा (1) के तहत अपने गठन के बाद किसी भी समय और समाधान योजना की पुष्टि से पहले, सूचना ज्ञापन तैयार करने से पहले किसी भी समय, निगमित देनदार को समाप्त करने का निर्णय ले सकती है। (3) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकरण 4 द्वारा अनुमोदित समाधान योजना [धारा 31 के तहत या धारा 54 एल की उप-धारा (1) के तहत] संबंधित निगमित ऋणी द्वारा उल्लंघन किया जाता है, वहां निगमित ऋणी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति, जिसके हित इस तरह के उल्लंघन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को परिसमापन आदेश के लिए आवेदन कर सकता है जैसा कि उप-धारा (1) के खंड (बी) के उप-खंड (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट है।

ग

डी.

ई.

च

(4) उप-धारा (3) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि निगमित ऋणी ने समाधान योजना के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, तो वह उप-धारा (1) के खंड (बी) के उप-खंड (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट परिसमापन आदेश पारित करेगा।

जी.

एच.

1240 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

(5) धारा 52 के अधीन रहते हुए, जब परिसमापन आदेश पारित किया जाता है, तो निगमित देनदार द्वारा या उसके विरुद्ध कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी:

बशर्ते कि निगमित ऋणी की ओर से परिसमापक द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के साथ कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

(6) उप-धारा (5) के प्रावधान ऐसे लेनदेन के संबंध में कानूनी कार्यवाही पर लागू नहीं होंगे जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा किसी भी वित्तीय क्षेत्र के नियामक के परामर्श से अधिसूचित किया जा सकता है।

ग

(7) इस धारा के तहत परिसमापन के आदेश को परिसमापक द्वारा परिसमापन प्रक्रिया के दौरान निगमित देनदार का व्यवसाय जारी रखने के अलावा, निगमित देनदार के अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिकों को निर्वहन की सूचना माना जाएगा।"

डी.

22. इस न्यायालय के. शशिधर बनाम इंडियन ओवरसीज बैंक 19 के निर्णय के अनुसार न्यायनिर्णायक प्राधिकरण "बाध्य है - आई एंड बी संहिता की धारा 33 (1) के तहत परिसमापन प्रक्रिया शुरू करें।"

यह भी माना गया कि संसद ने न्यायनिर्णायक को अधिकार नहीं दिया

सी. ओ. सी. के वाणिज्यिक निर्णय का विश्लेषण या मूल्यांकन करने के लिए अधिकार क्षेत्र या प्राधिकरण के साथ असहमति द्वारा समाधान योजना की अस्वीकृति के औचित्य की जांच करने के लिए बहुत कम प्राधिकरण।

ई.

वित्तीय लेनदार।" इस प्रकार, धारा 33 के तहत निर्दिष्ट किसी भी घटना की घटना पर, परिसमापन प्रक्रिया शुरू करनी होगी, निश्चित रूप से-इस मामले में कोई विकल्प नहीं है। एक बार फिर समिति में

एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के लेनदार बनाम सतीश कुमार गुप्ता और

च

या, 20 इस न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि आई. बी. सी. की धारा 30, 31 (2) और 60 (5) (सी) की व्याख्या पर परिसमापन कार्यवाही शुरू करने के संबंध में एन. सी. एल. टी. के पास कोई विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र है।

23. परिसमापन की शुरुआत के बाद, परिसमापन प्रक्रिया को पूरा करने और निगमित देनदार के अन्य मामलों का प्रबंधन करने के लिए एक परिसमापक नियुक्त किया जाना चाहिए। समाधान प्रक्रिया के संचालन के लिए नियुक्त आर. पी. को आम तौर पर परिसमापक के रूप में नियुक्त किया जाता है। परिसमापक की शक्तियाँ और कर्तव्य

जी.

19 के. शशिधर बनाम इंडियन ओवरसीज बैंक, 2019 (3) एससीआर 845।

20 एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के लेनदारों की समिति बनाम सतीश कुमार गुप्ता और अन्य।,
2019 (16) एससीआर 275।

एच.

1241

पास्चिमंचाल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम.रमन आई. एस. पी. ए. टी. प्राइवेट लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

क.

आई. बी. सी. की धारा 35 21 द्वारा निर्धारित हैं। इसमें लेनदारों के दावों का सत्यापन, निगमित देनदार की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, निगमित देनदार का व्यवसाय करना, निगमित देनदार की परिसंपत्तियों को ध्यान में रखना आदि शामिल हैं। परिसमापक को एक निर्धारित प्रारूप में नियुक्ति के 5 दिनों के भीतर एक सार्वजनिक घोषणा जारी करनी होती है; सार्वजनिक घोषणा का उद्देश्य लेनदारों और अन्य व्यक्तियों को कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए कहना है। निगमित देनदार के लेनदारों को परिसमापन प्रक्रिया शुरू होने के 30 दिनों के भीतर अपने दावे भेजने होते हैं। दावों की प्राप्ति के बाद परिसमापक को लेनदारों द्वारा प्रस्तुत दावों का सत्यापन करना होता है (धारा 39)। परिसमापक लेनदारों से सत्यापन के उद्देश्य से अपने दावों के संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए भी कह सकता है। परिसमापक को उचित सत्यापन के आधार पर दावों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार है। यदि परिसमापक किसी लेनदार के दावे को अस्वीकार या स्वीकार करता है, तो इस तरह के निर्णय (धारा 40) के 7 दिनों के भीतर लेनदार के साथ-साथ कॉर्पोरेट देनदार को भी सूचित किया जाना चाहिए। परिसमापक को समवर्ती रूप से यह निर्धारित करना होता है कि "परिसमापन संपदा" का गठन क्या है। धारा 36 (3) विभिन्न परिसंपत्तियों और दावों आदि को सूचीबद्ध करती है जो परिसमापन संपदा का निर्माण करती हैं। 22 दावों को स्वीकार करने के बाद परिसमापक को वितरण के उद्देश्य से दावों का मूल्य निर्धारित करना होता है।

ग

डी.

निगमित देनदार की परिसंपत्तियाँ।

21 "35. परिसमापक की शक्तियाँ और कर्तव्य।— (1) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन, परिसमापक के पास निम्नलिखित शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे, अर्थात्:- (क) सभी लेनदारों के दावों का सत्यापन करना;

ई.

(बी) कॉर्पोरेट देनदार की सभी संपत्तियों, संपत्ति, प्रभावों और कार्रवाई योग्य दावों को उसकी हिरासत में लेना या नियंत्रित करना;

(घ) निगमित देनदार की परिसंपत्तियों और संपत्तियों की रक्षा और संरक्षण के लिए ऐसे उपाय करना जो वह आवश्यक समझता है;

च

(ङ) निगमित देनदार के लाभदायक परिसमापन के लिए व्यवसाय को जारी रखना जो वह आवश्यक समझता है;

(च) धारा 52 के अधीन रहते हुए, सार्वजनिक नीलामी या निजी अनुबंध द्वारा परिसमापन में अचल और चल संपत्ति और निगमित देनदार के कार्रवाई योग्य दावों को किसी भी व्यक्ति या निगमित निकाय को ऐसी संपत्ति हस्तांतरित करने की शक्ति के साथ बेचना, या उसे पार्सल में इस तरह से बेचना जो निर्दिष्ट किया जाए:

जी.

बशर्ते कि परिसमापक परिसमापन में अचल और चल संपत्ति या निगमित देनदार के कार्रवाई योग्य दावों को किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं बेचेगा जो समाधान आवेदक होने का पात्र नहीं है।

22 धारा 36 (3) परिसमापन संपदा को निम्नलिखित के रूप में सूचीबद्ध करती है:

“(क) कोई भी परिसंपत्ति जिस पर निगमित देनदार का स्वामित्व अधिकार है, जिसमें सभी अधिकार और हित शामिल हैं, जैसा कि निगमित देनदार की तुलनपत्र में या एक सूचना उपयोगिता या रजिस्ट्री में रिकॉर्ड या किसी डिपॉजिटरी रिकॉर्डिंग प्रतिभूतियों में प्रमाणित है।

एच.

1242

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

24. परिसमापन विनियमों के विनियम 47 के संदर्भ में, परिसमापन कार्यवाही इसकी शुरुआत की तारीख से 1 वर्ष के भीतर पूरी की जानी चाहिए। यह आई. बी. सी. के तहत समाधान प्रक्रिया के लिए 330 दिनों की विस्तारित समय सीमा के विपरीत है।

25. दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान, एक सुरक्षित लेनदार को कोई भी कार्यवाही शुरू करके अपने बकाया का भुगतान करने की अनुमति नहीं है। यह धारा 14 (1) (सी) के आधार पर है जो एक अधिस्थगन अवधि को लागू करने में सक्षम बनाता है, जिसके दौरान एक सुरक्षित लेनदार को किसी भी सुरक्षा ब्याज को पूर्वनिर्धारित करने, पुनर्प्राप्त करने या लागू करने के लिए कोई कार्रवाई करने से रोक दिया जाता है। सुरक्षित लेनदारों के अधिकारों को केवल दिवालिया समाधान प्रक्रिया की विफलता की स्थिति में, परिसमापन के चरण में बहाल किया जाता है।

ग

बी. टी. हे 'डब्ल्यू एटर्नेल मैकेनिज्म'

26. आई. बी. सी. की धारा 53, जिसमें 'झरना तंत्र' शामिल है, परिसंपत्तियों के वितरण के क्रम का प्रावधान करती है। इसमें इस प्रकार कहा गया है:

डी.

“(1) संसद या तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किसी विधि में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, परिसमापन परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय को प्राथमिकता के निम्नलिखित क्रम में और ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी तरीके से वितरित किया जाएगा जो निर्दिष्ट किया जाए, अर्थात्:—

ई.

(क) दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत और परिसमापन लागत का पूरा भुगतान;

निगमित देनदार के या बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य माध्यम से, जिसमें निगमित देनदार की किसी सहायक कंपनी में रखे गए शेयर भी शामिल हैं;

((ख) ऐसी परिसंपत्तियाँ जो निगमित देनदार के कब्जे में हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं, जिनमें बोझ से भरी परिसंपत्तियाँ भी शामिल हैं लेकिन वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं;

च

(ग) मूल संपत्ति, चाहे वह चल हो या अचल।

(घ) अमूल्य परिसंपत्तियाँ जिनमें बौद्धिक संपदा, प्रतिभूतियाँ (निगमित देनदार की सहायक कंपनी में रखे गए शेयरों सहित) और वित्तीय साधन, बीमा पॉलिसियाँ, संविदात्मक अधिकार शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं;

(ई) अदालत या प्राधिकरण द्वारा स्वामित्व के निर्धारण के अधीन परिसंपत्तियाँ;

(च) इस अध्याय के अनुसार लेन-देन से बचने के लिए कार्यवाही के माध्यम से वसूल की गई कोई संपत्ति या उनका मूल्य;
जी.

(छ) निगमित देनदार की कोई संपत्ति जिसके संबंध में एक सुरक्षित लेनदार ने प्रतिभूति ब्याज छोड़ दिया है;

(ज) दिवाला प्रारम्भ होने की तिथि पर निगमित देनदार से संबंधित या उसमें निहित कोई अन्य संपत्ति; और

((ii) परिसमापन की सभी आय जब और जब उन्हें प्राप्त किया जाता है।"

एच.

1243

पाश्चिमांचाल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम.रमन आई. एस. पी. ए. टी. प्राइवेट लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

क.

(ख) निम्नलिखित ऋण जो निम्नलिखित के बीच और उनके बीच समान रूप से श्रेणीबद्ध होंगे:—

(i) परिसमापन शुरू होने की तारीख से पहले चौबीस महीने की अवधि के लिए श्रमिकों का बकाया; और

((ii) यदि ऐसे प्रतिभूत लेनदार ने धारा 52 में निर्धारित तरीके से प्रतिभूति छोड़ दी है, तो किसी प्रतिभूत लेनदार को देय ऋण;

(ग) परिसमापन शुरू होने की तारीख से पहले बारह महीने की अवधि के लिए श्रमिकों के अलावा अन्य कर्मचारियों को देय मजदूरी और कोई भी अवैतनिक बकाया;

ग

(घ) असुरक्षित लेनदारों को देय वित्तीय ऋण;

(ङ) निम्नलिखित देय राशि निम्नलिखित के बीच और उनके बीच समान रूप से क्रमबद्ध होगी:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

((i) परिसमापन प्रारंभ होने की तारीख से पहले की दो वर्ष की अवधि के पूरे या किसी भाग के संबंध में भारत की संचित निधि और राज्य की संचित निधि, यदि कोई हो, के कारण प्राप्त होने वाली राशि सहित केंद्र सरकार और राज्य सरकार को देय कोई भी राशि;

डी.

ई.

((ii) प्रतिभूति ब्याज लागू होने के बाद किसी भी राशि के भुगतान के लिए एक सुरक्षित लेनदार को देय ऋण;

(च) कोई शेष ऋण और देय राशि;

(छ) तरजीही शेयरधारक, यदि कोई हो; और

च

(ज) इक्विटी शेयरधारक या भागीदार, जैसा भी मामला हो।(2) समान श्रेणी के साथ उप-धारा (1) के तहत प्राप्तकर्ताओं के बीच कोई संविदात्मक व्यवस्था, यदि उस उप-धारा के तहत प्राथमिकता के क्रम को बाधित करती है, तो परिसमापक द्वारा इसकी अवहेलना की जाएगी।

जी.

(3) परिसमापक को देय शुल्क की कटौती उप-धारा (1) के तहत प्राप्तकर्ताओं के प्रत्येक वर्ग को देय आय से आनुपातिक रूप से की जाएगी और संबंधित प्राप्तकर्ता को प्राप्त आय को ऐसी कटौती के बाद वितरित किया जाएगा।

एच.

1244 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजन के लिए -

(i) एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि समान श्रेणी के प्राप्तकर्ताओं के वर्ग के संबंध में आय के वितरण के प्रत्येक चरण में, प्रत्येक ऋण का या तो पूरा भुगतान किया जाएगा, या प्राप्तकर्ताओं के एक ही वर्ग के भीतर समान अनुपात में भुगतान किया जाएगा, यदि आय पूर्ण रूप से ऋणों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है; और (ii) "श्रमिकों के बकाया" शब्द का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 326 में उसे सौंपा गया है।"

27. इसलिए जलप्रपात तंत्र के तहत वरीयताओं के पदानुक्रम में इंगित दावों की प्राथमिकता है:सबसे पहले, दिवाला समाधान प्रक्रिया की लागत और परिसमापन लागत; दूसरा, परिसमापन शुरू होने की तारीख से पहले 24 महीने की अवधि के लिए श्रमिकों का बकाया और ऐसे सुरक्षित लेनदार द्वारा प्रतिभूति छोड़ने की स्थिति में किसी सुरक्षित लेनदार को देय ऋण; तीसरा, परिसमापन शुरू होने की तारीख से पहले 12 महीने की अवधि के लिए श्रमिकों के अलावा अन्य कर्मचारियों को मजदूरी और कोई भी अवैतनिक बकाया; चौथा, असुरक्षित लेनदारों को देय वित्तीय ऋण; पांचवां, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को देय कोई भी राशि और प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन के बाद किसी भी राशि के लिए एक सुरक्षित लेनदार को देय ऋण; छठा, कोई भी शेष ऋण और बकाया; सातवां, प्राथमिकता शेयरधारक; और आठवां इक्विटी शेयरधारक या भागीदार।यह पदानुक्रम या प्राथमिकता का क्रम इस प्रकार सरकारी ऋणों [खंड (ई)] और परिचालन ऋणों [खंड (एफ)] को असुरक्षित वित्तीय लेनदारों के बकाया की तुलना में कम प्राथमिकता देता है।28. एक सुरक्षित लेनदार को देय ऋण, जब भी ऐसा सुरक्षित किया जाता है

ग

डी.

ई.

लेनदार ने धारा में निर्धारित तरीके से प्रतिभूति छोड़ दी है।

च

52" काफी उच्च प्राथमिकता प्राप्त करें (दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत के तुरंत बाद), जबकि अन्य मामलों में, यानी जब सुरक्षित लेनदार प्रतिभूति नहीं छोड़ता है, तो दावे की प्राथमिकता कम होती है [धारा 53]

(1) (ई) (ii)] प्रवर्तन के बाद भुगतान नहीं की गई किसी भी राशि के संबंध में

सुरक्षा हित में "।एक अन्य विशेषता यह है कि सरकार को देय राशियों (यानी, भारत की संचित निधि या किसी राज्य की संचित निधि में देय) को उसी तरीके से क्रमबद्ध किया जाता है जैसे कि सुरक्षित लेनदारों को जो अपने प्रतिभूति ब्याज (धारा 53 (1) (ई) (2)) को नहीं छोड़ते हैं।

जी.

29. दिवालियापन कानून सुधार समिति की रिपोर्ट, 2015, जिसके कारण आई. बी. सी. को तैयार किया गया और बाद में इसे लागू किया गया, में विशेष रूप से कहा गया है:

एच.

1245

पास्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड v. रमन आई. एस. पी. ए. टी. प्राइवेट लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

क.

“समिति ने ऋण की उपलब्धता को बढ़ावा देने और असुरक्षित वित्तपोषण (बांड बाजारों के विकास सहित) के लिए एक बाजार विकसित करने के लिए सभी प्रकार के सुरक्षित लेनदारों के अलावा असुरक्षित वित्तीय लेनदारों के नीचे प्राथमिकता पर परिसमापन में वितरण झरने में केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार को रखने की सिफारिश की है। दीर्घावधि में, इससे वित्त की उपलब्धता बढ़ेगी, पूंजी की लागत में कमी आएगी, उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा और तेजी से आर्थिक विकास होगा। सरकार को भी इस प्रक्रिया का लाभ होगा क्योंकि आर्थिक विकास से राजस्व में वृद्धि होगी। इसके अलावा, दक्षता में वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप प्रस्तावित दिवाला व्यवस्था के माध्यम से अधिक मूल्य पर कब्जा करने से अर्थव्यवस्था और सरकारी खजाने दोनों को अतिरिक्त लाभ होगा।”

ग

***** “परिसमापन की सामूहिक कार्रवाई में भाग लेने वाले शेष लेनदारों के लिए, समिति ने उन देनदारियों के झरने पर बहस की जो नई संहिता में परिसमापन में होनी चाहिए। विभिन्न क्षेत्राधिकारों में, अवलोकन यह है कि सुरक्षित लेनदारों की प्राप्ति पर पहली प्राथमिकता होती है, और ये आमतौर पर दिवाला समाधान और परिसमापन की लागतों का शुद्ध भुगतान किया जाता है। भारत में प्रथाओं को वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप लाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रस्तावित संहिता के उद्देश्यों को पूरा किया जाए, समिति ने सिफारिश की है कि परिसमापन में झरना निम्नानुसार होना चाहिए:

डी.

ई.

1. आई. आर. पी. और परिसमापन की लागत।

च

2. सुरक्षित लेनदारों और कामगारों का बकाया आई. आर. पी. की शुरुआत से तीन महीने तक सीमित था।

3. कर्मचारियों की सीमा तीन महीने तक कर दी गई है।

4. असुरक्षित वित्तीय लेनदारों के लिए देय, परिसमापन शुरू होने की तारीख से बारह महीने पहले शुरू होने और परिसमापन शुरू होने की तारीख से तीन महीने पहले समाप्त होने की अवधि के संबंध में श्रमिकों को देय ऋण;

जी.

5. परिसमापन शुरू होने की तारीख से पहले दो साल की अवधि के पूरे या किसी भी हिस्से के संबंध में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को देय कोई भी राशि;

एच.

1246 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

प्रतिभूति ब्याज लागू होने के बाद किसी भी बकाया राशि के लिए प्रतिभूति लेनदार का ऋण

6. बकाया कर्ज

7. शेयरधारकों के लिए अधिशेष।” 23

30. इसका स्पष्टीकरण दिवाला विधि समिति (2020) की रिपोर्ट में दिखाई देता है:24

“ 7.3.समिति ने नोट किया कि संहिता का उद्देश्य एक सामूहिक परिसमापन प्रक्रिया को बढ़ावा देना है, और इस उद्देश्य के लिए, यह सुरक्षित लेनदारों को धारा 53 (1) (बी) के तहत अपने बकाया की वसूली में दूसरी सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करके अपने सुरक्षा हित को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार, उन्हें संहिता के तहत सामान्य असुरक्षित लेनदारों के रूप में नहीं माना जाता है, जैसा कि वे कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत होते। यह ध्यान दिया गया कि, कुछ हद तक, इस प्रावधान का उद्देश्य सुरक्षा के लाभों को दोहराना है, भले ही इसे छोड़ दिया गया हो, ताकि समग्र मूल्य अधिकतमकरण को बढ़ावा दिया जा सके। हालांकि, अगर सुरक्षित लेनदारों को अपने सुरक्षा ब्याज का एहसास होता है, तो वे केवल अपने सुरक्षा ब्याज की सीमा तक ही वसूली करेंगे, और परिसमापन झरने की धारा 53 (1) (ई) के तहत भुगतान नहीं किए गए किसी भी अतिरिक्त बकाया का दावा करेंगे। इस प्रकार, समिति का विचार था कि इस प्रावधान का उद्देश्य उन सुरक्षित लेनदारों को प्रदान करना नहीं हो सकता था जो अपने प्रतिभूति ब्याज को छोड़ देते हैं, अपने पूरे ऋण पर पुनर्भुगतान की प्राथमिकता, चाहे उनके प्रतिभूति ब्याज की सीमा कुछ भी हो, क्योंकि यह एक ऐसे अधिकार का सम्मान करने के समान होगा जो कभी मौजूद नहीं था। इसके अलावा, यदि "किसी प्रतिभूत लेनदार को देय ऋण" प्रतिभूति की सीमा तक ही सीमित नहीं है, तो धारा 52 (1) (बी) के तहत दी गई प्राथमिकता के दुरुपयोग की व्यापक गुंजाइश होगी, क्योंकि जो लेनदार अपने ऋण की पूरी सीमा तक प्रतिभूत नहीं हैं, वे भी किसी भी प्रकार की प्रतिभूति रखने के तथ्य पर निर्भर होंगे, ताकि अन्य सभी हितधारकों को प्राथमिकता देते हुए अपने अवैतनिक बकाया की पूरी राशि की वसूली की जा सके।

ग

डी.

ई.

च

जी.

7.4.उपरोक्त चर्चा के आधार पर, समिति इस बात पर सहमत हुई कि इसके तहत सुरक्षित ऋणदाताओं की वसूली को प्राथमिकता दी जाएगी।

23 दिवालियापन कानून सुधार समिति की रिपोर्ट (2015), शीर्षक 5.5।8 - परिसमापन में भुगतान की प्राथमिकता स्थापित करना।

24 दिवाला विधि समिति की रिपोर्ट (2020)-शीर्षक 7.3-एक सुरक्षित लेनदार द्वारा प्रतिभूति ब्याज की प्राप्ति या त्याग। 76)।

एच.

1247

पास्चिमंचाल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम.रमन आई. एस. पी. ए. टी. प्राइवेट लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

क.

धारा 53 (1) (बी) (ii) केवल प्रतिभूति ब्याज के मूल्य की सीमा तक लागू होनी चाहिए जो प्रतिभूति लेनदार द्वारा छोड़ी जाती है। समिति की राय थी कि इस मुद्दे को ऊपर दिए गए तर्क के संदर्भ में स्पष्ट किया गया है और संहिता के प्रावधानों में आगे किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।”

31. आई. बी. सी. की प्रस्तावना स्पष्ट रूप से दावों की प्राथमिकता के आदेश के संबंध में कानून में बदलाव को मान्यता देती है, विशेष रूप से सरकारी बकाया के संबंध में:

“ उद्यमिता, ऋण की उपलब्धता को बढ़ावा देने और उद्यमिता को संतुलित करने के लिए ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए समयबद्ध तरीके से निगमित व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवालिया समाधान से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम।

ग

सरकारी देय राशि के भुगतान की प्राथमिकता के क्रम में परिवर्तन सहित हितधारकों के हितों को स्थापित करना

डी.

भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड और उससे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए।”

32. 2018 में सोलहवीं लोकसभा सत्र में संशोधन अधिनियम पर संसदीय बहसों से इस पहलू पर प्राप्त टिप्पणियों के जवाब में, दिवाला विधि समिति की रिपोर्ट में कहा गया है:

ई.

“संहिता की धारा 53 उन सुरक्षित लेनदारों को असुरक्षित वित्तीय लेनदारों से ऊपर रखती है जिन्होंने अपनी प्रतिभूति छोड़ दी है। इस प्रकार, असुरक्षित और सुरक्षित लेनदारों के बीच स्पष्ट अंतर किया गया है जो परिसमापन के मामले में भुगतान झरने के उद्देश्य से परिसमापन कार्यवाही में शामिल होते हैं। असुरक्षित लेनदारों को सुरक्षित लेनदारों से ऊपर रखा जाता है जिनके पास प्रतिभूतियों के प्रवर्तन के बाद अवैतनिक ऋण होते हैं क्योंकि यह माना जाता है कि ऐसे सुरक्षित लेनदारों ने परिसमापन कार्यवाही के बाहर अपनी प्रतिभूति को लागू करके अपने अधिकांश बकाया की वसूली की है। इसके अलावा, जैसा कि बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट में कहा गया है, असुरक्षित ऋणदाताओं के बकाया का संरक्षण जानबूझकर किया जाता है ताकि कॉर्पोरेट बांड और अन्य असुरक्षित ऋण के लिए बाजार को प्रोत्साहित किया जा सके।

च

जी.

श्रमिकों के बकाया के संबंध में, उन्हें उन सुरक्षित लेनदारों के साथ सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है जिनके पास है

एच.

1248 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

संहिता की धारा 53 में प्रदान किए गए भुगतान झरने के तहत आई. आर. पी. लागतों के बाद दूसरे स्थान पर अपनी सुरक्षा छोड़ दी।” 25

33. अपनी प्रतिभूति को प्राथमिकता में अधिक त्यागने वाले सुरक्षित लेनदारों को रखने का तर्क धारा 52 और 53 के संयुक्त पठन पर पाया जाता है। धारा 52 इस प्रकार है:

“परिसमापन कार्यवाहियों में सुरक्षित लेनदार।

(1) परिसमापन कार्यवाहियों में एक सुरक्षित लेनदार-(क) परिसमापन संपदा को अपना प्रतिभूति ब्याज दे सकता है और परिसमापक द्वारा परिसंपत्तियों की बिक्री से धारा 53 में निर्दिष्ट तरीके से आय प्राप्त कर सकता है; या

ग

(ख) इस धारा में निर्दिष्ट तरीके से अपने सुरक्षा हित का एहसास करना।

(2) जहां प्रतिभूति लेनदार को उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत प्रतिभूति ब्याज का एहसास होता है, वह परिसमापक को ऐसे प्रतिभूति ब्याज के बारे में सूचित करेगा और ऐसी प्रतिभूति ब्याज के अधीन संपत्ति की पहचान करेगा जिसे प्राप्त किया जाना है।

डी.

(3) इस धारा के तहत प्रतिभूति लेनदार द्वारा किसी भी प्रतिभूति ब्याज को प्राप्त करने से पहले, परिसमापक ऐसे प्रतिभूति ब्याज को सत्यापित करेगा और प्रतिभूति लेनदार को केवल ऐसे प्रतिभूति ब्याज को प्राप्त करने की अनुमति देगा, जिसका अस्तित्व या तो साबित किया जा सकता है -

ई.

(क) किसी सूचना उपयोगिता द्वारा बनाए गए ऐसे सुरक्षा हित के अभिलेखों द्वारा; या

((ख) बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य माध्यमों से।(4) एक सुरक्षित लेनदार ऐसे कानून के अनुसार सुरक्षित परिसंपत्तियों को लागू कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, निपटान कर सकता है, समझौता कर सकता है या सौदा कर सकता है जो प्राप्त किए जा रहे प्रतिभूति ब्याज और सुरक्षित लेनदार पर लागू होता है और इसके कारण ऋण की वसूली के लिए आय को लागू कर सकता है।

च

जी.

(5) यदि किसी सुरक्षित परिसंपत्ति को प्राप्त करने के क्रम में, किसी भी सुरक्षित लेनदार को प्रतिभूति का कब्जा लेने, बेचने या अन्यथा निपटान करने में निगमित देनदार या उससे जुड़े किसी व्यक्ति से प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, तो सुरक्षित लेनदार

25 दिवाला विधि समिति की रिपोर्ट (2018) (पृ. 87)।

एच.

1249

पास्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड v. रमन आई. एस. पी. ए. टी. प्राइवेट लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

क.

सुरक्षित लेनदार को उस समय लागू कानून के अनुसार ऐसे प्रतिभूति हित का एहसास कराने में सुविधा प्रदान करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन कर सकते हैं।

(6) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, उप-धारा (5) के तहत किसी सुरक्षित लेनदार से आवेदन प्राप्त होने पर ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो किसी सुरक्षित लेनदार को उस समय लागू कानून के अनुसार प्रतिभूति ब्याज प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक हो।

(7) जहां उप-धारा (4) के तहत प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन से आय के रूप में ऐसी राशि प्राप्त होती है जो प्रतिभूति प्राप्त लेनदार को देय ऋणों से अधिक है, तो प्रतिभूति प्राप्त लेनदार -

ग

(क) ऐसे अधिशेष के लिए परिसमापक को लेखा देना; और

(ख) ऐसी सुरक्षित परिसंपत्तियों के प्रवर्तन से प्राप्त किसी भी अधिशेष निधि को परिसमापक को भेजें।

डी.

(8) इस धारा में दिए गए तरीके से अपने प्रतिभूति हितों का एहसास करने वाले सुरक्षित लेनदारों से देय दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत की राशि, ऐसे सुरक्षित लेनदारों द्वारा किसी भी वसूली की आय से काट ली जाएगी, और वे ऐसी राशि परिसमापक को परिसमापन संपत्ति में शामिल करने के लिए हस्तांतरित करेंगे।

ई.

(9) जहां प्रतिभूत परिसंपत्तियों की प्राप्ति की आय प्रतिभूत लेनदार को देय ऋणों को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसे प्रतिभूत लेनदार के अवैतनिक ऋणों का भुगतान परिसमापक द्वारा धारा 53 की उप-धारा (1) के खंड (ई) में निर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा।"

च

34. धारा 52 सुरक्षित लेनदारों को परिसमापन प्रक्रिया (वह प्रक्रिया जिसके लिए परिसमापन विनियम 26 के विनियम 21 और 21 ए में निर्धारित किया गया है) में या तो अपने प्रतिभूति हित को छोड़ने या इसे लागू करने के लिए आगे बढ़ने का विकल्प देती है। बाद के विकल्प के मामले में,

जी.

26 परिसमापन विनियमों के उक्त प्रावधान इस प्रकार हैं:

"21. सुरक्षा हित साबित करना। प्रतिभूति ब्याज का अस्तित्व एक सुरक्षित लेनदार द्वारा इन आधार पर साबित किया जा सकता है -

(क) सूचना उपयोगिता में उपलब्ध अभिलेख, यदि कोई हो;

(बी) कंपनियों के पंजीयक द्वारा जारी शुल्क पंजीकरण का प्रमाण पत्र; या (सी) भारत के प्रतिभूतिकरण संपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित की केंद्रीय रजिस्ट्री के साथ शुल्क पंजीकरण का प्रमाण।

एच.

1250

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

सुरक्षित लेनदार को पहले निर्धारित समय के भीतर (30 दिन, परिसमापन विनियमों की अनुसूची II के प्रपत्र सी या डी में) अपना विकल्प इंगित करना होगा। परिसमापक तब धारा 52 (3) के अनुसार, सुरक्षित लेनदार को अनुमति दे सकता है।

प्रतिभूति ऋणों के रूप में ऐसे बकाया का भुगतान करना जो मौजूद साबित हो। उस पर

परिसमापक द्वारा मंजूरी, सुरक्षित लेनदार धारा 52 (4) के तहत अपने दावे को लागू करने के लिए आगे बढ़ सकता है। यदि प्रक्रिया के दौरान प्रतिरोध होता है, तो सुरक्षित लेनदार एन. सी. एल. टी. [धारा 52 (5) और (6)] से संपर्क कर सकता है। प्रवर्तन पर, प्राप्त की गई किसी भी अतिरिक्त राशि को परिसमापक [धारा 52 (7)] को दिया जाना चाहिए।

35. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि एक सुरक्षित लेनदार को परिसमापन प्रक्रिया की शुरुआत में एक परिकलित निर्णय लेना पड़ता है, चाहे या

ग

अपने सुरक्षित ब्याज को न छोड़ना। यदि वह ऐसा करता है, तो उसका बकाया श्रेणीबद्ध होता है।

झरना तंत्र में उच्च। यदि वह अपने प्रतिभूति हित को न छोड़ने का विकल्प चुनता है, और इसके बजाय सफलता के बिना इसे लागू करने के लिए आगे बढ़ता है या प्रवर्तन की प्रक्रिया में अपने सभी बकाया का भुगतान करने में असमर्थ है, तो उसे करना होगा

तब बल प्राथमिकता में कम रहता है, और परिसमापक द्वारा परिसमापन संपत्ति की प्राप्ति पर परिसंपत्तियों के वितरण की प्रतीक्षा करता है।

डी.

उसके देय राशि का संतुलन। 36. इस प्रकार परिकल्पित प्रक्रिया, एक सुरक्षित लेनदार के बकाया की वसूली के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाती है। यदि वे सुरक्षा छोड़ने का विकल्प चुनते हैं, तो उनकी प्राथमिकता उच्च श्रेणी की होती है; यदि वे ऐसी सुरक्षा को लागू करना चाहते हैं, तो परिसमापक द्वारा सूचना और सत्यापन के अधीन, वे ऐसा करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। कम गिरावट की स्थिति में, वे प्राथमिकता में कम स्थान पर होते हैं। यह कारण प्रतीत होता है, जैसा कि 2018 में संसदीय बहसों के परिणामस्वरूप टिप्पणियों के जवाब में दिए गए स्पष्टीकरण से स्पष्ट है, कि सुरक्षित लेनदारों ने अपने सुरक्षा हित को नहीं छोड़ने का विकल्प चुना है।

ई.

“यह अनुमान लगाया गया है कि ऐसे सुरक्षित लेनदारों ने परिसमापन के बाहर अपनी प्रतिभूति को लागू करके अपने अधिकांश बकाया की वसूली की है।

च

कार्यवाही "। 27 इसमें ठोस तर्क है, क्योंकि जो इसका विकल्प चुनते हैं

21A. प्रतिभूति हित का अनुमान। (1) एक सुरक्षित लेनदार परिसमापक को परिसमापन संपदा को अपने प्रतिभूति हित को छोड़ने या अनुसूची II के प्रपत्र सी या प्रपत्र डी में उसके प्रतिभूति हित का एहसास करने के अपने निर्णय के बारे में सूचित करेगा।

बशर्ते कि, जहां कोई सुरक्षित लेनदार परिसमापन शुरू होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्णय की सूचना नहीं देता है, तो प्रतिभूति ब्याज के तहत आने वाली परिसंपत्तियों को परिसमापन संपदा का हिस्सा माना जाएगा।

जी.

(2) जहां एक प्रतिभूति लेनदार अपने प्रतिभूति ब्याज का एहसास करने के लिए आगे बढ़ता है, वह धारा 53 की उप-धारा (1) के खंड (ए) और खंड (बी) के उप-खंड (आई) के तहत देय राशि के लिए उतना ही भुगतान करेगा जितना उसने प्रतिभूति ब्याज छोड़ने की स्थिति में साझा किया होगा।"

27 सुप्रा नोट 25.

एच.

1251

पास्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड v. रमन आई. एस. पी. ए. टी. प्राइवेट लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एस. रवींद्र भाट, जे.]

क.

‘ऐसा करने के लिए ‘स्टैंड आउट’ और प्रतिभूति ब्याज को लागू करने की अनुमति है; अतिरिक्त वसूली की स्थिति में, उन्हें परिसमापन कार्यवाही में वितरण के लिए इस तरह की अतिरिक्त राशि को सूचित करना होगा और सौंपना होगा; यदि वे अपने बकाया की वसूली करने में असमर्थ हैं, तो ऐसे सुरक्षित लेनदारों को निम्न श्रेणी में रखा जाता है।

37. मोजर बेयर करमचारी में इस अदालत का हालिया फैसला

यूनियन टीआर।अध्यक्ष महेश चंद शर्मा बनाम भारत संघ और

ओआरएस 28 ने आईबीसी के झरने के प्रावधानों को विस्तार से निपटाया था, हालांकि श्रमिकों के बकाया के दावों की प्राथमिकता के संदर्भ में। इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

“66. ...संहिता की धारा 52 की उप-धारा (1) एक सुरक्षित लेनदार को दो विकल्प देती है। सबसे पहले, परिसमापन कार्यवाही में सुरक्षित लेनदार अपने प्रतिभूति ब्याज को छोड़ सकता है और परिसमापक द्वारा परिसंपत्तियों की बिक्री से आय को संहिता की धारा 53 में निर्दिष्ट तरीके से प्राप्त कर सकता है। दूसरा विकल्प सुरक्षा हित का एहसास करना है, लेकिन संहिता की धारा 52 में निर्दिष्ट तरीके से। संहिता की धारा 52 की उप-धारा (2) में कहा गया है कि जहां सुरक्षित लेनदार को प्रतिभूति हित का एहसास होता है, वह परिसमापक को ऐसे प्रतिभूति हित के बारे में सूचित करेगा और ऐसे प्रतिभूति हित की प्राप्ति के अधीन संपत्ति की पहचान करेगा। परिसमापक को प्रतिभूति ब्याज का सत्यापन करना होता है और वह प्रतिभूति लेनदार को ऐसे प्रतिभूति हित का एहसास करने की अनुमति देगा, जो या तो किसी सूचना उपयोगिता द्वारा बनाए गए ऐसे प्रतिभूति हित के रिकॉर्ड से या बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए गए ऐसे अन्य माध्यमों से साबित होता है। संहिता की धारा 52 की उप-धारा (4) में कहा गया है कि सुरक्षित लेनदार प्राप्त किए जा रहे प्रतिभूति हित और सुरक्षित लेनदार के लिए लागू होने वाले कानून के अनुसार सुरक्षित संपत्ति को लागू कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, निपटान कर सकता है, समझौता कर सकता है या उसके साथ सौदा कर सकता है। प्रतिभूत लेनदार को तदनुसार अपने देय ऋणों की वसूली के लिए आय का उपयोग करना होता है। हमें संहिता की धारा 52 की उप-धारा (5) का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह उस कार्रवाई से संबंधित है जो प्रतिभूत लेनदार उस स्थिति में कर सकता है जब उसे निगमित देनदार या उससे जुड़े किसी अन्य व्यक्ति से प्रतिभूति को कब्जे में लेने, बेचने या अन्यथा निपटाने में प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। धारा की उप-धारा (6)

ग

डी.

ई.

च

जी.

28 मोजर बेयर करमचारी यूनियन थ.अध्यक्ष महेश चंद शर्मा बनाम संघ

भारत और ओआरएस।, 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 547

एच.

1252 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

क.

52 यह संहिता तब लागू होती है जब कोई न्यायनिर्णायक प्राधिकारी संहिता की धारा 52 की उप-धारा (5) के तहत आवेदन प्राप्त करता है। तथापि, संहिता की धारा 52 की उप-धारा (7) महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कहा गया है कि जहां प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन पर, आय के रूप में एक राशि प्रतिभूति लेनदार के देय ऋणों से अधिक है, वहां प्रतिभूति लेनदार ऐसी प्रतिभूति संपत्तियों के प्रवर्तन से परिसमापक को अतिरिक्त/अधिशेष राशि का लेखा देगा और उसका भुगतान करेगा। धारा में दिए गए तरीके से अपने सुरक्षा हितों का एहसास करने वाले सुरक्षित लेनदारों से देय दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत की राशि, ऐसे सुरक्षित लेनदारों द्वारा किसी भी वसूली की आय से काट ली जानी है। उन्हें हस्तांतरित किया जाना है और परिसमापन संपदा में शामिल किया जाना है। संहिता की धारा 52 की उप-धारा (9) में कहा गया है कि जहां प्रतिभूत परिसंपत्तियों की वसूली के लिए आय प्रतिभूत लेनदार को देय ऋणों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसे प्रतिभूत लेनदार के अवैतनिक ऋणों का भुगतान परिसमापक द्वारा संहिता की धारा 53 की उप-धारा (1) के खंड (ई) में निर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा।

ग

डी.

67. उन श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए जहां सुरक्षित लेनदार संहिता की धारा 53 के तहत आने वाले अपने प्रतिभूति हित को नहीं छोड़ता है, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियमन 21 ए को अधिनियमित किया गया है, और यह आवश्यक है कि सुरक्षित लेनदार, जो संहिता की धारा 52 के अनुसार अपने प्रतिभूति ब्याज का एहसास करने का विकल्प चुनता है, को संहिता की धारा 53 की धारा 53 के खंड (ए) और उप-खंड (आई) के खंड (बी) के तहत देय राशि के लिए समय और उसमें निर्धारित तरीके के भीतर परिसमापक को भुगतान करना होगा। श्रमिकों का बकाया, तब भी जब सुरक्षित लेनदार संहिता की धारा 52 के तहत आगे बढ़ने का विकल्प चुनता है, इसलिए संहिता की धारा 53 की उप-धारा (1) के उप-खंड (बी) के संदर्भ में संरक्षित है।

ई.

च

जी.

69. अब हम संहिता की धारा 53 की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जो एक गैर-अस्थायी खंड के साथ शुरू होती है और यह बताती है कि संसद या किसी राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किसी भी कानून में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद

एच.

1253

पाश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड v. रमन आई. एस. पी. ए. टी. प्राइवेट लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

उस समय प्रवृत्त परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय को प्राथमिकता के क्रम में, जो निर्धारित है, और ऐसी अवधि और ऐसी रीति के भीतर वितरित किया जाएगा जो निर्दिष्ट की जाए। संहिता की धारा 53 की उप-धारा (1) का परिणाम यह है कि जब उक्त प्रावधान लागू होता है तो यह सुरक्षित लेनदार सहित पक्षों के अधिकारों पर हावी हो जाएगा। संहिता की धारा 53 पूर्ण और व्यापक संहिता है जो परिसंपत्तियों का संग्रह सुनिश्चित करती है और फिर लेनदारों को भुगतान करने का तरीका प्रदान करती है। यहां तक कि सुरक्षा हित पर लागू होने वाली सुरक्षित परिसंपत्तियों को लागू करने, प्राप्त करने, निपटाने, समझौता करने या उनसे निपटने के लिए संहिता की धारा 53 के तहत आने वाले सुरक्षित लेनदार के अधिकारों को भी कम किया जाता है और समझौता किया जाता है।

ग

70. धारा 53 की उप-धारा (1) का खंड (ए) दिवाला समाधान प्रक्रिया लागतों और परिसमापन लागतों से संबंधित है जिनका पूरा भुगतान किया जाना है। उक्त खंड के संबंध में कोई शिकायत या मुद्दा नहीं उठाया जा सकता है। धारा 53 की उप-धारा (1) के खंड (बी) में कहा गया है कि परिसमापन शुरू होने की तारीख से पहले चौबीस महीने की अवधि के लिए श्रमिकों के बकाया के रूप में देय ऋण और ऐसे सुरक्षित लेनदार द्वारा संहिता की धारा 52 में निर्धारित तरीके से प्रतिभूति छोड़ने की स्थिति में सुरक्षित लेनदार को देय ऋण श्रमिकों और सुरक्षित लेनदारों के बीच और उनके बीच समान रूप से रैंक करेंगे। संहिता की धारा 53 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि 'श्रमिकों के बकाया' का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 326 में दिया गया है। दूसरे शब्दों में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 326 का स्पष्टीकरण शामिल किया गया है और संहिता की धारा 53 की उप-धारा (1) के खंड (बी) में निर्धारित झरने तंत्र पर लागू होता है। यहाँ जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि संहिता की धारा 53 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत, श्रमिकों का बकाया परिसमापन शुरू होने की तारीख से पहले चौबीस महीने की अवधि के लिए है। परिसमापन प्रारंभ तिथि, जैसा कि संहिता की धारा 5 की उप-धारा (17) के संदर्भ में परिभाषित किया गया है, समय के संदर्भ में बहुत पहले की है और इसे समाप्त होने की तारीख के साथ मेल नहीं खाना चाहिए। यह श्रमिकों के हित में है। संहिता की धारा 53 के स्पष्टीकरण के खंड (i) में कहा गया है कि जहां वर्ग के संबंध में आय का वितरण -

डी.

ई.

च

जी.

एच.

1254 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

समान श्रेणी के प्राप्तकर्ताओं में से प्रत्येक ऋण का भुगतान या तो पूर्ण रूप से किया जाएगा या प्राप्तकर्ताओं के समान वर्ग के भीतर समान अनुपात में भुगतान किया जाएगा, यदि आय पूर्ण रूप से ऋणों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। प्रत्यक्षतः, खंड बहुत न्यायसंगत और निष्पक्ष है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि श्रमिकों के अलावा अन्य कर्मचारियों को देय मजदूरी और अवैतनिक बकाया खंड (सी) में आता है, जो संहिता की धारा 53 के खंड (बी) से उप-धारा (1) के नीचे है। उन्हें केवल परिसमापन शुरू होने की तारीख से पहले बारह महीने की अवधि के लिए मजदूरी और अवैतनिक बकाया का भुगतान किया जाना है, और वह भी केवल तभी जब संहिता की धारा 53 की उप-धारा (1) के खंड (ए) और (बी) के संदर्भ में भुगतान करने के बाद अधिशेष निधि उपलब्ध हो। संहिता की धारा 53 की उप-धारा (1) का खंड (डी) असुरक्षित लेनदारों को देय वित्तीय ऋणों से संबंधित है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार आदि को देय राशियों और प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन के बाद किसी भी राशि के लिए एक सुरक्षित लेनदार को देय ऋण को संहिता की धारा 53 की उप-धारा (1) के खंड (ई) में एक साथ जोड़ा गया है, और उन्हें दोनों के बीच और उनके बीच समान रूप से क्रमबद्ध किया जाना है। शेष ऋण और बकाया संहिता की धारा 53 की उप-धारा (1) के खंड (च) में आते हैं। वरीयता शेयरधारक संहिता की धारा 53 की उप-धारा (1) के खंड (जी) के तहत आते हैं और इक्विटी शेयरधारक या भागीदार संहिता की धारा 53 की उप-धारा (1) के खंड (एच) के तहत आते हैं। संहिता की धारा 53 की उप-धारा (2) में कहा गया है कि उप-धारा (1) के तहत प्राप्तकर्ताओं के बीच समान श्रेणी के साथ कोई भी संविदात्मक व्यवस्था, यदि उक्त उप-धारा के तहत प्राथमिकता के क्रम को बाधित करती है, तो परिसमापक द्वारा उसकी अवहेलना की जाएगी।

ग

डी.

ई.

च

71. जलप्रपात तंत्र एक संरचित गणितीय सूत्र पर आधारित है, और पदानुक्रम कई योग्यताओं के साथ प्राथमिकता के क्रम में ऋणों के भुगतान के संदर्भ में बनाया गया है, किसी भी प्रावधान को निरस्त करने या जलप्रपात तंत्र में पदानुक्रम को पुनर्व्यवस्थित करने से कई यात्राएं हो सकती हैं और समग्र रूप से संतुलन के काम में बाधा आ सकती है और अस्थिरता पैदा हो सकती है। जलप्रपात तंत्र में हर बदलाव से सुरक्षित ऋणदाताओं, परिचालन ऋणदाताओं और यहां तक कि केंद्रीय और राज्य ए के अधिकारों और हितों के संतुलन पर व्यापक प्रभाव पड़ना तथ्य है।

जी.

एच.

1255

पास्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड v. रमन आई. एस. पी. ए. टी. प्राइवेट लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

सरकारों/तथ्यों के आधार पर, कुछ मामलों में, संहिता में झरना तंत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 326 के तहत प्रदान किए गए पदानुक्रम की तुलना में अधिक फायदेमंद हो सकता है और इसके विपरीत। इसलिए, हम संकोच करते हैं और याचिकाकर्ताओं के तर्कों को स्वीकार नहीं करते हैं।

72. संहिता कानून के जैविक विकास पर आधारित है और परिसमापन को नियंत्रित करने वाली संहिता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक व्यापक परामर्श प्रक्रिया का एक उत्पाद है। इसने सभी व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने और हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिए एक व्यापक और समयबद्ध ढांचा पेश किया। परिसमापन में भुगतान की प्राथमिकता निर्धारित करने में संहिता के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत भारत में प्रथाओं को वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप लाना था। जलप्रपात तंत्र में, दिवाला समाधान प्रक्रिया और परिसमापन की लागत के बाद, सुरक्षित लेनदार श्रमिकों के बकाया की एक निर्धारित अवधि के साथ उच्चतम प्राथमिकता साझा करते हैं। संहिता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों और संहिता की धारा 53 द्वारा निर्धारित झरना तंत्र के संदर्भ में श्रमिकों के अवैतनिक बकाया को पर्याप्त और महत्वपूर्ण रूप से संरक्षित किया जाता है। सुरक्षित लेनदार द्वारा प्रतिभूति के त्याग या गैर-अधिग्रहण के किसी भी मामले में, श्रमिकों के हितों को संहिता के तहत संरक्षित किया जाता है। वास्तव में, सुरक्षित लेनदार काफी हद तक बाल काट रहे हैं और कर्मचारियों को संहिता की धारा 53 के अनुसार न्यायसंगत और उचित तरीके से न्यायसंगत आधार पर मुआवजा दिया जा रहा है। संहिता सुरक्षित लेनदारों के अधिकारों को संतुलित करती है, जो वित्तीय संस्थान हैं जिनमें आम जनता ने धन का निवेश किया है, और यह भी सुनिश्चित करती है कि एक व्यवहार्य कंपनी की आर्थिक गतिविधि और पुनरुद्धार बाधित न हो क्योंकि वह वित्तीय संकट का सामना कर चुकी है या गिर गई है। संहिता दक्षता वृद्धि और परिणामस्वरूप अधिक से अधिक मूल्य प्राप्ति के माध्यम से अर्थव्यवस्था और राजकोष दोनों में अतिरिक्त लाभ लाने पर केंद्रित है। आर्थिक मामलों में, कानून निर्माता को एक व्यापक अक्षांश दिया जाता है और न्यायालय व्यावहारिक अनुभवों और कानून निर्माताओं द्वारा देखी गई अन्य समस्याओं के आधार पर ऐसे विधानों में प्रयोग करने की अनुमति देता है। इस तरह के कानून को चुनौती देते हुए, न्यायालय एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण नहीं अपनाता है। कुछ बलिदान हमेशा अधिक से अधिक भलाई के लिए किए जाने चाहिए, और जब तक कि इस तरह के बलिदान प्रथम दृष्टया स्पष्ट न हों।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

1256 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

स्पष्ट रूप से मनमाना के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कठोर और असमान, इनमें अदालत द्वारा हस्तक्षेप किया जाएगा।"

38. इसलिए यह स्पष्ट है कि आई. बी. सी. के प्रावधानों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है, और सुरक्षित लेनदारों को विकल्प दिए जाते हैं, और परिसमापन कार्यवाही में अन्य लेनदारों के साथ उनके हितों को संतुलित किया जाता है।

2003 ए. सी. टी. और 2005 सी. ओ. डी. ई. के तहत सी. आर. पारिस्थितिकी तंत्र

39. 2003 के अधिनियम की धारा 56 के आधार पर, किसी भी स्थिति में

व्यक्ति की उपेक्षा "बिजली के लिए किसी भी शुल्क या बिजली के लिए देय शुल्क के अलावा किसी अन्य राशि का भुगतान करने के लिए" उसे बिजली की आपूर्ति, संचरण या वितरण या पहियों के संबंध में "(के बाद

ग

एक स्पष्ट पंद्रह दिनों का 'लिखित नोटिस') और उसके प्रति पूर्वाग्रह के बिना

मुकदमा द्वारा ऐसे शुल्क या अन्य राशि की वसूली का अधिकार ", एक लाइसेंसधारी

(पी. वी. वी. एन. एल. जैसे वितरण लाइसेंसधारी सहित) ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति को बिजली की आपूर्ति बंद करने का अधिकार है।

40. 2003 के अधिनियम की धारा 181 (2) (x) के आधार पर, राज्य आयोगों को विनियम बनाने का अधिकार है। धारा 50 राज्य आयोगों को बिजली शुल्क की वसूली, बिजली शुल्क के बिलिंग के लिए अंतराल, भुगतान न करने पर बिजली की आपूर्ति को काटने आदि के लिए "बिजली आपूर्ति संहिता" तैयार करने का अधिकार देती है। **2003 के अधिनियम और संबंधित** संहिताओं के ये प्रावधान **2003 के अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार के लाइसेंसधारियों द्वारा बकाया की वसूली के लिए** कानूनी ढांचा बनाते हैं। वर्तमान मामले में उत्तर प्रदेश राज्य आयोग ने **2005 की आपूर्ति संहिता तैयार की थी। 2005 की** संहिता का खंड **4.3 (च) (iv)** प्रासंगिक है, जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार प्रदान करता है:

डी.

ई.

"बकाया राशि कंपनी की परिसंपत्तियों पर पहला शुल्क होगा, और लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि यह नए आवेदक के साथ एक समझौते में किया गया है।"

च

41. 2005 की संहिता का खंड 6.15 अधिनियमित करता है कि बकाया की वसूली उत्तर प्रदेश सरकार विद्युत उपक्रम (देय वसूली) अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार होगी:

" 6.15 बकाया राशि की वसूली

जी.

(क) अनुज्ञप्तिधारक को देय भुगतान अधिनियम की धारा 56 के प्रावधान के अनुसार और यू. पी. सरकारी विद्युत उपक्रम (देय वसूली) अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार भूमि राजस्व के बकाया के अनुसार, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है, वसूल किया जाएगा।

एच.

1257

पास्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड v. रमन आई. एस. पी. ए. टी. प्राइवेट लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

क.

(ख) तत्काल लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, किसी भी उपभोक्ता से देय कोई भी राशि उस तारीख से दो साल की अवधि के बाद वसूली योग्य नहीं होगी जब तक कि ऐसी राशि को आपूर्ति किए गए बिजली शुल्क के बकाया के रूप में लगातार वसूली योग्य नहीं दिखाया गया है, और लाइसेंसधारी बिजली की आपूर्ति में कटौती नहीं करेगा।

(व्याख्या: जिस तारीख से इस तरह के शुल्क 'पहले देय' हो जाते हैं, उसकी सही व्याख्या की जानी चाहिए। यदि उपभोक्ता की स्थापना के नियमित मीटर रीडिंग/निरीक्षण के परिणामस्वरूप, इस कोड या टैरिफ अनुसूची के अनुसार लगाए गए ऐसे शुल्क/दंड, उपभोक्ता द्वारा ऐसे बिल की प्राप्ति के 15 दिनों के बाद पहले देय हो जाएंगे, और ऐसा बिल उपभोक्ता को उस श्रेणी के उपभोक्ता के लिए दो बिलिंग चक्र के बाद प्रदान किया जाएगा।)"

ग

42. जैसा कि पहले ऊपर कहा गया है, कॉर्पोरेट देनदार ने पी. वी. वी. एन. एल. के साथ 11.02.2010 पर बिजली की आपूर्ति के लिए एक समझौता किया, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि बकाया बिजली उसकी परिसंपत्तियों पर 'शुल्क' का गठन करेगी।²⁹ यह 2005 की संहिता के खंड 4.3 (च) (iv) के अनुसार था। समझौते 30 के खंड 8 में यह भी उल्लेख किया गया है कि पक्ष 2003 के अधिनियम द्वारा शासित होंगे।

डी.

43. के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड 31 में इस अदालत के हाल के एक फैसले में उन परिस्थितियों की जांच की गई जिसमें इस तरह के 'आरोप' को कानून में गठित किया जा सकता है, और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:

ई.

“107. नतीजतन, सामान्य कानून में, परिसर के हस्तांतरणकर्ता को पिछले मालिक के बकाया के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि बिजली बकाया स्वचालित रूप से परिसर पर शुल्क नहीं बन जाता है। ऐसी कार्रवाई केवल तभी अनुमत है जब आपूर्ति की वैधानिक शर्तें बिजली के नए कनेक्शन का दावा करने वाले बाद के खरीदार से बकाया बिजली की वसूली को अधिकृत करती हैं, या यदि हस्तांतरणकर्ता पर वैधानिक शुल्क के निर्माण के लिए कानून का कोई स्पष्ट प्रावधान है।”

च

जी.

29 समझौते का खंड 5, पैराग्राफ 2 में निकाला गया है।

30 समझौते का खंड 8 इस प्रकार है: “यह समझौता इसके द्वारा शासित होगा -

विद्युत अधिनियम, 2003 अपने सभी संशोधनों के साथ, उस समय लागू भारत के विभिन्न अन्य कानून, लेकिन यूपीईआरसी के विभिन्न विनियमों तक सीमित नहीं, जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य पर लागू होता है और इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।”

31 के. सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 603।

एच.

1258

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आरोप का सृजन आवश्यक रूप से 2003 के अधिनियम या पूर्ण विधान के एक स्पष्ट प्रावधान पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि मूल कानून के तहत अधिकृत उचित रूप से बनाए गए विनियमों द्वारा बनाया जा सकता है। इन परिस्थितियों में, पी. वी. वी. एन. एल. का यह तर्क कि आपूर्ति संहिता के खंड 4.3 (च) (iv) के आधार पर, पक्षों के बीच समझौते में शर्तों के साथ पढ़ा जाता है, निगमित देनदार की परिसंपत्तियों पर शुल्क लगाया गया था, योग्य है। एन. सी. एल. टी. के विवादित आदेश को सावधानीपूर्वक पढ़ने से यह भी पता चलता है कि इस स्थिति को स्वीकार कर लिया गया था। यह एन. सी. एल. ए. टी. के आदेश से स्पष्ट है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि पी. वी. वी. एन. एल. भी कानून के अनुसार 'सुरक्षित परिचालन लेनदार' की परिभाषा के तहत आता है। यह निष्कर्ष विचलित नहीं हुआ था, बल्कि विवादित आदेश द्वारा पुष्टि की गई थी। इन परिस्थितियों में, इस निष्कर्ष पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि पी. वी. वी. एन. एल. एक सुरक्षित लेनदार है।

44. परिसमापक के वकील ने प्रस्तुत किया था कि पी. वी. वी. एन. एल. का बकाया तकनीकी रूप से "सरकार" का बकाया था, और इस प्रकार मंजूरी की प्राथमिकता के क्रम में एक निचले स्थान पर था। अभिव्यक्ति "सरकारी बकाया" आई. बी. सी. में परिभाषित नहीं है-यह केवल प्रस्तावना में जगह पाता है। हालाँकि, इस तरह के बकाया का गठन धारा 53 (1) (ई) के तहत 'झरना तंत्र' में किया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ कहता है।

डी.

कि, "भारत की संचित निधि और राज्य की संचित निधि के कारण प्राप्त होने वाली राशि सहित केंद्र सरकार और राज्य सरकार को देय कोई भी राशि"

ई.

धारा 53 (1) के खंड (ए) से (डी) में वर्णित लेनदारों के वर्ग के लिए प्राथमिकता में निम्न स्थान पर है। इस प्रकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बकाया की एक अलग गणना या विनिर्देश मौजूद है,

अन्य लेनदारों के अलावा एक वर्ग के रूप में, जिसमें ऐसे लेनदार भी शामिल हैं जिनके पास सुरक्षित ब्याज हो सकता है (जिसके संबंध में राशि देय हो सकती है)

उनके लिए)। आई. बी. सी. के अधिनियमन से पहले की विभिन्न रिपोर्टों में सांविधिक कर, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार को देय अन्य बकाया राशि, या किसी भी सरकार के लिए संचित निधि में देय राशियों के कारण सरकार को ऋणों की प्राथमिकता को कम करने का बार-बार उल्लेख करने का अर्थ है कि ये बकाया अलग हैं और इन्हें सुरक्षित लेनदारों को देय राशि से अलग माना जाना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सामान्य खंड अधिनियम, 1897 द्वारा परिभाषित किया गया है। पूर्व को धारा 3 (8), 32 और बाद वाले को धारा द्वारा परिभाषित किया गया है।

च

जी.

32 (8) "केंद्र सरकार "-

(क) संविधान के प्रारंभ से पहले की गई किसी भी चीज के संबंध में, गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल इन काउंसिल, जैसा भी मामला हो, से तात्पर्य है और इसमें शामिल होंगे:

एच.

1259

पास्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड v. रमन आई. एस. पी. ए. टी. प्राइवेट लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

3 (60).33 सरकारों के बीच अंतर को इस अदालत के पिछले फैसलों द्वारा मान्यता दी गई है और बनाए रखा गया है। उदाहरण के लिए, श्रीकांत बनाम वसंतराव और अन्य, 34 में इस अदालत ने रेखांकित किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत एक इकाई या निगम "राज्य" हो सकता है, फिर भी, इसकी विशिष्ट इकाई, अन्य उद्देश्यों के लिए, हमेशा बनी रहती है, और तथ्य-निर्भर होती है:

"दोनों संविधान के भाग-3 के सीमित उद्देश्य के लिए अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' की परिभाषा का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा, अनुच्छेद 12 के तहत भारत सरकार, प्रत्येक राज्य की सरकार का उल्लेख करते हुए 'राज्य' की बहुत समावेशी परिभाषा।

(i) भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 124 की उप-धारा (1) के तहत किसी प्रांत की सरकार को सौंपे गए कार्यों के संबंध में, उस उप-धारा के तहत उसे दिए गए प्राधिकरण के दायरे में कार्य करने वाली प्रांतीय सरकार; और

ग

((ख) मुख्य आयुक्त के प्रांत के प्रशासन के संबंध में, मुख्य आयुक्त, जो उक्त अधिनियम की धारा 94 की उप-धारा (3) के तहत उसे दिए गए अधिकार के दायरे में कार्य करता है; और

डी.

(ख) संविधान के प्रारंभ के बाद किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में, राष्ट्रपति का अर्थ होगा; और इसमें शामिल होंगे: -

(i) संविधान के अनुच्छेद 258 के खंड (1) के तहत किसी राज्य की सरकार को सौंपे गए कार्यों के संबंध में, उस खंड के तहत उसे दिए गए प्राधिकरण के दायरे में कार्य करने वाली राज्य सरकार;

((ख) भाग ग राज्य 2 [संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के प्रारंभ से पहले] के प्रशासन के संबंध में, मुख्य आयुक्त या उपराज्यपाल या किसी पड़ोसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकरण जो, यथास्थिति, संविधान के अनुच्छेद 239 या अनुच्छेद 243 के तहत उसे या उसे दिए गए अधिकार के दायरे में कार्य करता है; और

ई.

((ग) किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के संबंध में, उसका प्रशासक संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत उसे दिए गए अधिकार के दायरे में कार्य करता है।

33 (60) "राज्य सरकार ", -

(क) संविधान के प्रारंभ से पहले की गई किसी भी चीज के संबंध में, इसका अर्थ होगा, भाग क राज्य में, संबंधित प्रांत की प्रांतीय सरकार, भाग ख राज्य में, संबंधित तिथि पर अधिकृत प्राधिकारी या व्यक्ति जो संबंधित राज्य में कार्यकारी सरकार का प्रयोग करने के लिए अधिकृत है, और भाग ग राज्य में, केंद्र सरकार;

च

((ख) [संविधान के प्रारंभ के बाद और संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के प्रारंभ से पहले] किए गए किसी भी कार्य के संबंध में, इसका अर्थ होगा, भाग ए राज्य में, राज्यपाल, भाग बी राज्य में, राजप्रमुख और भाग सी राज्य में, केंद्र सरकार;

जी.

(ग) संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के प्रारंभ के बाद किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में, इसका अर्थ होगा, किसी राज्य में, राज्यपाल और किसी केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र सरकार; और संविधान के अनुच्छेद 258 ए के तहत भारत सरकार को सौंपे गए कार्यों के संबंध में, उस अनुच्छेद "34 श्रीकांत बनाम वसंतराव और अन्य के तहत उसे दिए गए अधिकार के दायरे में कार्य करने वाली केंद्र सरकार शामिल होगी।, 2006 (1) एससीआर 496

एच.

1260 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

राज्य और स्थानीय और अन्य प्राधिकरण, यह स्पष्ट करते हैं कि एक 'राज्य सरकार' और एक स्थानीय या अन्य प्राधिकरण अलग हैं और वे केवल संविधान के भाग-III के उद्देश्य के लिए एक सामान्य परिभाषा के तहत आते हैं। इस न्यायालय ने संविधान के अन्य भागों में आने वाले 'राज्य' या 'राज्य सरकार' शब्दों की व्याख्या के लिए संविधान के भाग-III (और भाग-IV) में दी गई 'राज्य' की विस्तारित परिभाषा को लागू करने से लगातार इनकार कर दिया है। जबकि "राज्य" शब्द में संविधान के भाग-3 (या भाग-4) के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार के साथ-साथ सांविधिक या अन्य प्राधिकरण भी शामिल हो सकते हैं, "राज्य सरकार" शब्द अपने सामान्य अर्थों में किसी स्थानीय या सांविधिक प्राधिकरण को शामिल नहीं करता है।

45. इस न्यायालय का निर्णय, के नगर आयुक्त में

दम दम नगरपालिका और अन्य बनाम भारतीय पर्यटन विकास निगम और अन्य, 35 ने देखा कि, "प्रमुख सार्वजनिक उपयोगिताओं के मामले में, विभिन्न संस्थाओं के तहत वैधानिक निगम बनाए गए थे।

डी.

अधिनियम बनाए गए और कुछ उदाहरण दिए गए जैसे कि सड़क परिवहन निगम, विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 के तहत बिजली बोर्ड आदि। अदालत ने कहा कि:

"इन वैधानिक निगमों और कंपनियों को उन गतिविधियों को जारी रखने में सक्षम बनाने के लिए जो अब तक सरकारों द्वारा की जाती थीं, प्रासंगिक संपत्तियों, परिसंपत्तियों और देनदारियों को ऐसे नए निगमों को हस्तांतरित कर दिया गया था। उन्हें व्यापार के आधार पर काम करना था, करों का भुगतान करना था और अपने निर्माण और संविधान को उचित ठहराना था। ये निगम, चाहे कानून के तहत बनाए गए हों या कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत हों, अलग-अलग न्यायिक संस्थाएं हैं जो अपनी संपत्तियों के मालिक हैं, जिनके पास अपनी निधि है, जो धन उधार लेने और उधार देने में सक्षम हैं और किसी भी अन्य निगम की तरह अनुबंध करने में सक्षम हैं। कई मामलों में, इन निगमों की पूरी शेयर पूंजी सरकार के स्वामित्व में होती है, चाहे वह केंद्र हो या राज्य। कुछ मामलों में, प्रमुख हिस्सेदारी सरकार की होती है और कुछ निजी हिस्सेदारी भी होती है। कुछ सांविधिक निगमों के मामले में, उन्हें बनाने वाले अधिनियम में किसी भी शेयर पूंजी का प्रावधान नहीं था, हालांकि इसे एक

ई.

च

जी.

35 दम दम नगर पालिका के नगर आयुक्त और अन्य बनाम भारतीय पर्यटन विकास निगम और अन्य, 1995 (5) एससीसी 251।

एच.

1261

पास्चिमंचाल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम. रमन आई. एस. पी. ए. टी. प्राइवेट लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

क.

ऐसी अवधारणा के साथ जाने वाली सभी आवश्यक और आनुषंगिक शक्तियों के साथ निगमित निकाय। अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम के तहत बनाया गया एक ऐसा निगम है जिसकी कोई शेयर पूंजी नहीं है, लेकिन जिसकी अपनी संपत्तियां, अपना कोष, खाते, कर्मचारी हैं और जो ऋण देने और उधार लेने और अनुबंध करने में सक्षम है।"

46. लेनदारों के अन्य वर्ग का विशिष्ट उल्लेख जिनका बकाया वैधानिक है, जैसे कि श्रमिकों या कर्मचारियों को देय बकाया।

भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान निधि "धारा के तहत

36(4), जो इन गणना की गई राशियों को परिसमापन से बाहर करता है, विशेष रूप से स्पष्ट करता है कि कानून के तहत बकाया सभी बकाया को 'सरकारी' बकाया के रूप में नहीं माना जाता है। दूसरे शब्दों में, सांविधिक निगमों को देय देय राशि जो "केंद्र या राज्य सरकार को देय राशि" के विवरण के भीतर नहीं आती है, जैसे कि उदाहरण के लिए उन कानूनों द्वारा बनाए गए निगमों को देय राशि जिनके पास अलग-अलग न्यायिक इकाई है, लेकिन जिनके बकाया देय सरकारी बकाया नहीं हैं या जो संबंधित समेकित निधियों में देय हैं, वे एक अलग आधार पर हैं। ऐसे निगम परिचालन लेनदार या वित्तीय लेनदार या सुरक्षित लेनदार हो सकते हैं जो उनके द्वारा निगमित देनदार के साथ किए गए लेनदेन की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरी ओर, देय या

कोषागार में जमा किए जाने की आवश्यकता, जैसे कर, शुल्क, आदि जो मोटे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 265 के दायरे में आते हैं, 'सरकारी बकाया' हैं और इसलिए आई. बी. सी. की धारा 53 (1) (एफ) के अंतर्गत आते हैं।

ग

डी.

ई.

47. पी. वी. वी. एन. एल. की निस्संदेह सरकारी भागीदारी है। हालाँकि, यह इसे सरकार या 'राज्य सरकार' का हिस्सा नहीं बनाता है। इसके कार्यों को अन्य संस्थाओं, निजी और सार्वजनिक दोनों द्वारा दोहराया जा सकता है। बिजली की आपूर्ति, उत्पादन, पारेषण और बिजली के वितरण को 2003 के अधिनियम के संदर्भ में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर उदार बनाया गया है। निजी संस्थाओं को लाइसेंस रखने का अधिकार है। इस संदर्भ में, इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि वितरण लाइसेंसधारियों के रूप में निजी भागीदारी काफी व्यापक है। इन कारणों से, यह माना जाता है कि वर्तमान मामले में, पी. वी. वी. एन. एल. को देय बकाया या देय राशि आई. बी. सी. की धारा 53 (1) (एफ) के विवरण के भीतर नहीं आती है।

च

जी.

48. पी. वी. वी. एन. एल. ने निर्णय इंद्रधनुष पत्रों (ऊपर) पर भरोसा किया था। उस मामले में, शामिल मुद्दा गुजरात मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 48 की व्याख्या थी, जिसमें यह अधिनियमित किया गया था कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कर या जुर्माने के लिए देय कोई भी राशि 'प्रथम' होगी।

एच.

1262

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

ऐसे विक्रेता या व्यक्ति की संपत्ति पर प्रभार। निगमित देनदार ने अपने कर बकाया के भुगतान में चूक की थी और वसूली की कार्यवाही शुरू की गई थी। इस बीच, दिवाला प्रक्रिया शुरू हो गई थी। समाधान प्रक्रिया के दौरान, राज्य कर अधिकारियों ने दावा किया कि देय राशि पहले अर्जित की जानी थी और आई. बी. सी. की धारा 53 के अलावा धारा 48 पर भरोसा किया। राज्य ने तर्क दिया कि राज्य अधिनियम में गैर-अस्थाई खंड और आई. बी. सी. में गैर-अस्थाई खंड विभिन्न क्षेत्रों में संचालित होते हैं, और राज्य अधिनियम की धारा 48 के आधार पर राज्य को 'सुरक्षित लेनदार' के रूप में माना जाना चाहिए। इसे एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. ने खारिज कर दिया था। हालाँकि, इस अदालत ने आई. बी. सी. की धारा 30 और 31 और कुछ अन्य प्रावधानों पर ध्यान दिया और कहा कि एन. सी. एल. टी. ने अपनी टिप्पणियों में गलती की है। यह माना गया था कि:

ग

“56. जी. वी. ए. टी. अधिनियम की धारा 48 आई. बी. सी. की धारा 53 या किसी अन्य प्रावधान के विपरीत या असंगत नहीं है। धारा 53 (1) (बी) (ii) के तहत, एक सुरक्षित लेनदार को देय ऋण, जिसमें जी. वी. ए. टी. अधिनियम के तहत राज्य शामिल होगा, परिसमापन शुरू होने की तारीख से पहले 24 महीने की अवधि के लिए श्रमिकों के बकाया के कारण ऋण सहित अन्य निर्दिष्ट ऋणों के साथ समान रूप से रैंक करना है।

डी.

57. जैसा कि ऊपर देखा गया है, राज्य जी. वी. ए. टी. अधिनियम के तहत एक सुरक्षित लेनदार है। आई. बी. सी. की धारा 3 (30) सुरक्षित लेनदार को एक ऐसे लेनदार के रूप में परिभाषित करती है जिसके पक्ष में प्रतिभूति ब्याज जमा किया जाता है।

इस तरह के सुरक्षा हित कानून के संचालन द्वारा बनाए जा सकते हैं।आई. बी. सी. में सुरक्षित लेनदार की परिभाषा किसी भी सरकारी या सरकारी प्राधिकरण को बाहर नहीं करती है।

ई.

58. हम यह ठहराने के लिए विवश हैं कि अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अपीलार्थी के आवेदन/अपील को अस्वीकार करने में कानूनी रूप से गलती की है।जैसा कि ऊपर देखा गया है, दावा दायर करने में देरी दावे को अस्वीकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है।"

च

49. इंद्रधनुष पत्र (उपरोक्त) ने धारा 53 के तहत 'झरना तंत्र' पर ध्यान नहीं दिया-इस प्रावधान को निर्णय में जोड़ा या निकाला नहीं गया था।इसके अलावा, इंद्रधनुष पत्र (ऊपर) समाधान प्रक्रिया के संदर्भ में थे न कि परिसमापन के दौरान।धारा 53, जैसा कि पहले कहा गया था, विभिन्न वर्गों के लेनदारों के दावों के पदानुक्रम या प्राथमिकता प्रदान करने वाले जलप्रपात तंत्र को लागू करती है।धारा 53 का सावधानीपूर्वक अभिकल्पना ए की लागतों और खर्चों के बाद दूसरे स्थान पर सुरक्षित लेनदारों और श्रमिकों को देय राशियों का पता लगाती है।

जी.

एच.

1263

पास्चिमंचाल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम.रमन आई. एस. पी. ए. टी. प्राइवेट लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

परिसमापन प्रक्रिया के दौरान देय परिसमापक।हालांकि, सरकार को देय देय राशि सुरक्षित लेनदारों और यहां तक कि असुरक्षित और परिचालन लेनदारों से बहुत कम है।इस डिजाइन को या तो इंद्रधनुष पत्रों (ऊपर) में अदालत के ध्यान में नहीं लाया गया था या पूरी तरह से छूट गया था।किसी भी स्थिति में, निर्णय में आई. बी. सी. के उन प्रावधानों पर ध्यान नहीं दिया गया है जो केंद्र या राज्य सरकार को देय बकाया की तुलना में सुरक्षित लेनदारों को देय बकाया को उच्च स्तर पर मानते हैं।

50. गुजरात मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 निस्संदेह देय और देय या बकाया राशि के संबंध में एक शुल्क बनाता है।(वर्तमान मामले में, धारा 53 (1) (ई) में सरकारी बकाया की एक विशिष्ट गणना के अभाव में) यह अभिनिर्धारित करना संभव होगा कि राज्य को 'सुरक्षित लेनदार' के रूप में माना जाना है।हालांकि, एक ओर सुरक्षित लेनदार को देय राशि का अलग और विशिष्ट व्यवहार और दूसरी ओर सरकार को देय बकाया स्पष्ट रूप से संसद के इरादे को दर्शाता है कि बाद वाले के साथ अलग व्यवहार किया जाए-और वर्तमान मामले में, कम प्राथमिकता दी जाए।जैसा कि पहले देखा गया है, यह इरादा अधिनियम की प्रस्तावना को पढ़ने से भी स्पष्ट होता है।

ग

डी.

51. वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों के अनुसार, जब कोई अधिनियम दो अलग-अलग अभिव्यक्तियों का उपयोग करता है, तो उन्हें एक ही अर्थ के रूप में नहीं माना जा सकता है।यह सदस्य, राजस्व बोर्ड में आयोजित किया गया था।

v. एंथनी पॉल बेंथल 36 कि: "जब एक कानून में अलग-अलग महत्व के दो शब्दों का उपयोग किया जाता है, तो लगातार दो प्रावधानों में, यह बनाए रखना मुश्किल होगा कि उनका उपयोग एक ही अर्थ में किया गया है।

ई.

यह विचार बृहन्मुंबई में एक बाद के फैसले में परिलक्षित होता है।

च

महानगर पालिका और अन्न बनामविलिंगटन स्पोर्ट्स क्लब एंड ओआरएस। 37

52. वर्तमान निर्णय द्वारा व्यक्त किए गए विचारों में समर्थन मिलता है

एबीजी शिपयार्ड बनाम केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड 38 के परिसमापक सुंदरेश भट्ट के रूप में निर्णय की सूचना दी गई। उस मामले में, अनुभाग

142 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 का ए मुद्दा था-अधिकारियों ने प्रस्तुत किया था कि इसे देय बकाया को संपत्ति पर 'पहले शुल्क' के रूप में माना जाना था

जी.

36 सदस्य, राजस्व बोर्ड बनाम एंथनी पॉल बेंथल (1955) 2 एससीआर 842।

37 बृहन्मुंबई महानगर पालिका और अन्न बनामविलिंगटन स्पोर्ट्स क्लब एंड ओआरएस।, (2013)

(16) एससीआर 216।

38 सुंदरेश भट्ट, एबीजी शिपयार्ड बनाम केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के परिसमापक और

सीमा शुल्क, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1101।

एच.

1264

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

संबंधित निर्धारिती का। समाधान प्रक्रिया में, यह तर्क दिया गया कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 ने प्रधानता प्राप्त कर ली है और इसे प्रभावी बनाया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने आई. बी. सी. की धारा 238 के प्रबल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया:

“55. स्पष्टता के लिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है:

(क) क्या आई. बी. सी. के प्रावधान सीमा शुल्क अधिनियम पर हावी होंगे, और यदि हैं, तो किस हद तक?

आई. बी. सी. सीमा शुल्क अधिनियम पर इस हद तक प्रबल होगा कि एक बार आई. बी. सी. की धारा 14 या 33 (5) के संदर्भ में स्थगन लागू हो जाने के बाद, प्रतिवादी प्राधिकरण के पास सीमा शुल्क और अन्य शुल्कों की मात्रा का आकलन/निर्धारण करने के लिए केवल एक सीमित अधिकार क्षेत्र है। प्रत्यर्थी प्राधिकारी के पास बिक्री/ज़बती के माध्यम से बकाया की वसूली शुरू करने की शक्ति नहीं है, जैसा कि सीमा शुल्क अधिनियम के तहत प्रदान किया गया है। (ख) क्या प्रत्यर्थी माल पर स्वामित्व का दावा कर सकता है और परिसमापन प्रक्रिया शुरू होने पर सीमा शुल्क अधिनियम के संदर्भ में माल बेचने के लिए नोटिस जारी कर सकता है?

ग

डी.

नकारात्मक जवाब दिया।

56. उपरोक्त चर्चाओं के आधार पर, हमारे निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

ई.

(i) एक बार जब आई. बी. सी. की धारा 14 या 33 (5) के संदर्भ में स्थगन लगाया जाता है, तो प्रतिवादी प्राधिकरण के पास सीमा शुल्क और अन्य शुल्कों की मात्रा का आकलन/निर्धारण करने के लिए केवल एक सीमित अधिकार क्षेत्र होता है। प्रत्यर्थी प्राधिकारी के पास बिक्री/जब्त के माध्यम से बकाया की वसूली शुरू करने की शक्ति नहीं है, जैसा कि सीमा शुल्क अधिनियम के तहत प्रदान किया गया है। (ii) इस तरह के मूल्यांकन के बाद, प्रत्यर्थी प्राधिकारी को आई. बी. सी. के तहत निर्धारित समय अवधि के सख्त अनुपालन में, निर्धारित प्रक्रिया के संदर्भ में अपने दावों (सीमा शुल्क बकाया/परिचालन ऋण से संबंधित) को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

च

जी.

(iii) किसी भी मामले में, आई. आर. पी./आर. पी./परिसमापक आई. बी. सी. के संदर्भ में उचित तरीके से निपटने के लिए प्रतिवादी प्राधिकरण से तुरंत सामान सुरक्षित कर सकता है।

एच.

1265

पास्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड v. रमन आई. एस. पी. ए. टी. प्राइवेट लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

क.

इसी तरह, डंकन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम. ए. जे. एग्रोकेम 39, सेक्शन

16 चाय अधिनियम, 1953 का जी, जिसके लिए केंद्र सरकार की पूर्व सहमति (समापन कार्यवाही शुरू करने के लिए) की आवश्यकता थी, आई. बी. सी. द्वारा ओवरराइड किया गया था। इसी तरह, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि आई. बी. सी. की धारा 238 विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों को ओवरराइड करती है, इसके बावजूद कि आई. बी. सी. में दो विशिष्ट प्रावधान हैं जो गैर-अबाधित खंडों (यानी धारा 173 और 174) के साथ खुलते हैं। आई. बी. सी. की प्रधानता के संबंध में कानून की स्थिति सुंदरेश भट्ट और डंकन इंडस्ट्रीज (ऊपर) में चर्चा की गई स्थिति के समान है [यह भी देखें कि: नवान्वेषी

उद्योग (उपरोक्त), सी. आई. टी. बनाम मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड 40, घनश्याम मिश्रा एंड संस (पी) लिमिटेड बनाम। एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड 41, और जगमोहन बजाज बनाम शिवम फ्रेग्रेंस प्राइवेट लिमिटेड 42]।

ग

53. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाता है कि इंद्रधनुष पत्रों (उपरोक्त) पर निर्भरता का अपीलार्थी को कोई लाभ नहीं है। इस अदालत के विचार में, उस फैसले को केवल उस मामले के तथ्यों तक ही सीमित रखना होगा।

डी. ई. सी. ओ. एम. पी. एन. आई. एस. ए. सी. टी. की धारा 77 का परिणाम

डी.

54. अंत में, परिसमापक ने आग्रह किया था कि आरोप के पंजीकरण के बिना, परिसमापन कार्यवाही के तहत इसे लागू नहीं किया जा सकता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 77 इस प्रकार है:

“77. शुल्कों आदि को पंजीकृत करने का कर्तव्य-(1) यह कर्तव्य होगा -

भारत के भीतर या बाहर, अपनी संपत्ति या परिसंपत्तियों या भारत में या भारत के बाहर स्थित अपने किसी भी उपक्रम पर, चाहे वह मूर्त हो या अन्यथा, शुल्क लगाने वाली प्रत्येक कंपनी, कंपनी और शुल्कधारक द्वारा हस्ताक्षरित शुल्क के विवरण को, यदि कोई हो, ऐसे शुल्क के भुगतान पर ऐसे रूप में और ऐसी तरीके से शुल्क बनाने वाले उपकरणों के साथ, जो उसके निर्माण के तीस दिनों के भीतर पंजीयक के साथ पंजीकृत करेगी: बशर्ते कि पंजीयक, कंपनी द्वारा एक आवेदन पर, ऐसे अतिरिक्त शुल्क के

भुगतान पर ऐसा पंजीकरण करने की अनुमति दे सकता है जो निर्धारित किया जाए: बशर्ते कि यदि पंजीकरण इस तरह के निर्माण के तीन सौ दिनों की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो कंपनी निम्नलिखित के अनुसार समय बढ़ाने की मांग करेगी:

ई.

च

जी.

39 डंकन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम. ए. जे. एग्रीकेम (2019) 9 एस. सी. सी. 725।

40 (2018) 18 एससीसी 786 41 [2021] 13 एससीआर 737

42 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन एन. सी. एल. ए. टी. 413

एच.

1266 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

धारा 87: बशर्ते कि शुल्क का कोई भी बाद का पंजीकरण वास्तव में शुल्क पंजीकृत होने से पहले किसी भी संपत्ति के संबंध में अर्जित किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(2) जहां उप-धारा (1) के तहत पंजीयक के पास कोई प्रभार पंजीकृत है, वह कंपनी को और, यथास्थिति, उस व्यक्ति को, जिसके पक्ष में प्रभार सृजित किया गया है, ऐसे प्रपत्र और उस तरीके से ऐसे प्रभार के पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा जो कंपनी को निर्धारित किया जाए।

(3) तत्काल प्रवृत्त किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, परिसमापक या किसी अन्य लेनदार द्वारा किसी कंपनी द्वारा सृजित किसी भी शुल्क को तब तक ध्यान में नहीं रखा जाएगा जब तक कि वह उप-धारा (1) के तहत विधिवत पंजीकृत न हो और ऐसे शुल्क के पंजीकरण का प्रमाण पत्र उप-धारा (2) के तहत पंजीयक द्वारा नहीं दिया जाता है।

ग

(4) उप-धारा (3) की कोई भी बात किसी शुल्क द्वारा सुरक्षित धन के पुनर्भुगतान के लिए किसी अनुबंध या दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।"

डी.

55. धारा 78 में कहा गया है कि जब कोई कंपनी जिसकी संपत्ति शुल्क के अधीन है, उसे पंजीकृत करने में विफल रहती है, तो शुल्क धारक (या कंपनी की संपत्तियों पर शुल्क का हकदार व्यक्ति) इसका पंजीकरण करा सकता है। आई. बी. सी. की धारा 3 (31) "सुरक्षा हित" को व्यापक रूप से परिभाषित करती है। इस अदालत की राय में परिसमापक इस स्तर पर इस पहलू का आग्रह नहीं कर सकता है, क्योंकि एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के समवर्ती निष्कर्षों के अनुसार पी. वी. वी. एन. एल. एक सुरक्षित लेनदार है।

ई.

56. रिकॉर्ड से आगे पता चलता है कि एन. सी. एल. टी. द्वारा अपना आदेश पारित करने के बाद, अपीलार्थी ने 10.04.2018 पर अपने दावे को प्राथमिकता दी। उस आवेदन के आधार पर, परिसमापक ने अपने दिनांक 1 के आदेश में संशोधन के लिए एन. सी. एल. टी. के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, और तर्क दिया था कि पी. वी. वी. एन. एल. भी कानून के अनुसार परिसमापन कार्यवाही में अपने बकाया की वसूली में 'सुरक्षित परिचालन लेनदार' की परिभाषा के तहत आता है। आवेदन में हितधारकों की सूची में संशोधन की मांग की गई थी। आवेदन की अनुमति दी गई। इन तथ्यात्मक घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 77 के तहत आरोपों के गैर-पंजीकरण के तथ्य के संबंध में परिसमापक की प्रस्तुतियों पर निर्णय देना उचित नहीं समझता है।

च

जी.

एच.

1267

पास्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड v. रमन आई. एस. पी. ए. टी. प्राइवेट लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एस. रवींद्र भाट, जे.]

क.

वी. सी. कन्कूजन

57. उपरोक्त कारणों से, यह माना जाता है कि अपील विफल होने के योग्य है। साथ ही परिसमापक को पी. वी. वी. एन. एल. द्वारा किए गए दावे पर कानून द्वारा आवश्यक तरीके से निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है। यह अपीलार्थी को ऐसा अवसर प्रदान करने के बाद, जो कानून के तहत आवश्यक है, इस निर्णय की घोषणा की तारीख से 10 सप्ताह के भीतर प्रक्रिया को पूरा करेगा।

58. अपील को उपरोक्त निर्देश के अधीन, लागत पर आदेश के बिना खारिज कर दिया जाता है।

ग

दिव्या पांडे

याचिका खारिज की जाती है।

(सहायक: शेवाली मोंगा, एलसीआरए)

डी.

ई.

च

जी.

एच.